



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230035
CG-DL-E-29092021-230035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/आश्विन 6, 1943

No. 293]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्या: एडी (ओआई) - 33/2020

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'डेकोर पेपर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/38/2020-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डेकोर पेपर" (जिसे आगे यहां "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उनपर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे

"नियमावली" या एडी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए मै.आईटीसी लि. पेपरबोर्ड एंड स्पेशियलिटी पेपर्स डिविजन (जिसे आगे यहां "आवेदक" अथवा याचिकाकर्ता या "घरेलू उद्योग" या डीआई भी कहा गया है) से एक आवेदन पत्र (जिसे आगे यहां "याचिका" भी कहा गया है) प्राप्त हुआ।

3. और यतः संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को प्रथम दृष्टया दर्शाने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितम्बर 2020 की अधिसूचना सं 6/38/2020-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2020 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जाँच की शुरूआत के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति ई-मेल की है और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार रखने का अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य हितवद्ध पक्षकारों को भी अनुरोध किए जाने पर ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।
- ङ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
 - i. चांगले केयुआन पेपर कंपनी लिमिटेड
 - ii. हांगजो हुआवोन न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - iii. किंगडेकोर (झेजियांग) कं., लि.
 - iv. किफेंग न्यू मटेरियल लि.
 - v. जियानहे कं., लि.
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों की सूची सहित उन्हें भी भेजी गई थी।
- छ. संबद्ध जांच की शुरूआत की अधिसूचना के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके प्रत्युत्तर दिया है:
 - i. किंगडेकोर (झेजियांग) कं., लि., चीन जन गण
 - ii. किफेंग न्यू मटेरियल लि., चीन जन गण

- iii. शेडोंग वॉक्सिंग औहुआ स्पेशल पेपर कं., लि.
 - iv. जियानहे कं., लि.,
 - v. जेजियांग जियानहे न्यू मैटेरियल्स सेल्स कं., लि.
 - vi. जिबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि.
- ज. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी, जिसमें नियमावली के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगी गई थी।
- i. सेंचुरी प्लाईवोर्ड्स आई लिमिटेड
 - ii. कलर एक्सपर्ट्स
 - iii. फकीरसन पपकेम प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. फैसी रोटो प्रिंट
 - v. ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - vi. जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी
 - vii. मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - viii. मारुति डेकोर
 - ix. मारुति पेपर केम
 - x. मैच ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xi. मैचवेल
 - xii. एमबीई पेपर प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xiii. माइक्रोटेक प्रिंटेज प्राइवेट लिमिटेड
 - xiv. पिक्सेल प्रिंटर
 - xv. प्रिन्टेक इंडस्ट्रीज
 - xvi. सांबलिया इम्पेक्स एलएलपी
 - xvii. सराफ सेल्स कॉर्पोरेशन
 - xviii. साया पेपर प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
 - xix. शिंडेकोर
 - xx. शिवम पेपर प्रिंट
 - xxi. सिल्वर पेपर प्रिंट
 - xxii. स्लीक माइका प्राइवेट लिमिटेड
 - xxiii. स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xxiv. सरफेस डेकोर प्राइवेट लिमिटेड
 - xxv. तनिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

- xxvi. यूनिक डेकोर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- xxvii. विनायक डेकोर
- xxviii. विजन प्रिंटर
- झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को परिचालित करने और नियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी:
- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
 - भारतीय उद्योग परिसंघ
 - फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
 - इंडियन लैमिनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- ञ. संबद्ध जांच की शुरुआत के जवाब में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके उत्तर दिया है:
- आइका लैमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - डेको माइका लिमिटेड
 - फकीरसन पपकेम प्राइवेट लिमिटेड
 - जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी
 - मैच ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - सराफ सेल्स कॉर्पोरेशन
- ट. प्राधिकारी ने निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरू करने की सूचना देते हुए जांच की शुरुआत की सूचना प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के अनुरोध के साथ भेजी :
- पुदुमजी पेपर उत्पाद
 - श्री कृष्णा पेपर्स
- ठ. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रकोप और भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा आवागमन पर लगाये गए परिणामी प्रतिबंधों के कारण प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए अन्य हितवद्ध पक्षकारों को परिचालित किया।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से विगत तीन वर्षों और जॉच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार व्योरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जॉच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों पर भरोसा किया है।
- ढ. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की ईष्टतम उत्पादन लागत और संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर निकाली गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे आगे 'पीओआई' भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) की है। क्षति अवधि में 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल होगी।

- त. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संबद्ध वस्तु को विभिन्न किस्मों में आयात किया जा रहा है, आवेदक ने क्षति जाँच के लिए पीसीएन-से-पीसीएन की तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है।
- थ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। सभी हितवद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार बताएं।
- द. प्राधिकारी ने दिनांक 3 मई, 2021 के पत्र द्वारा पीसीएन को अंतिम रूप दिया, जिसके अनुसरण में हितवद्ध पक्षों ने पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत की।
- ध. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रकोप और भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा आवागमन पर लगाये गए परिणामी प्रतिबंधों के कारण प्राधिकारी ने मौके पर सत्यापन के जरिए सूचना का वास्तविक निरीक्षण नहीं किया। प्राधिकारी द्वारा आवेदक/उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का डेस्क सत्यापन, जहां तक आवश्यक समझा गया, किया गया था। इस जांच के प्रयोजन के लिए जहां तक आवश्यक समझा गया, केवल ऐसी सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया गया है।
- न. प्राधिकारी ने एडी नियमों के नियम 6(6) और व्यापार नोटिस संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के अनुसार, हितवद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए 16 जून, 2021 को प्राधिकरण के समक्ष मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक सुनवाई की।
- त. उपर्युक्त मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के बारे में 23 जून, 2021 तक लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज करें, इसके बाद 29 जून, 2021 तक प्रत्युत्तर, यदि कोई हों प्रस्तुत करें। इस जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक हितवद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों और प्रत्युत्तरों पर विचार किया गया है।
- प. इस जांच के अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बना है, को 15.09.2021 को हितवद्ध पक्षों को जारी किया गया था और हितवद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 22.09.2021 तक का समय दिया गया था। हितवद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- फ. इस जांच के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके साक्ष्य के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक होने की सीमा तक, इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।
- व. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- भ. जहां कहीं किसी हितवद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/समुक्तियों दर्ज की हैं।
- म. प्राधिकारी ने इस स्तर पर दिए गए सभी तर्कों और सभी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझे जानेकी सीमा तक विचार किया है और इन अंतिम जांच परिणामों में निष्कर्षों में उन्हें आधार बनाया है।
- य. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** चिह्न गोपनीय आधार पर किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- र. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और समान वस्तु

5. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

3. विचाराधीन उत्पाद विचाराधीन उत्पाद "40-130 जीएसएम, के रील फार्म में कोट न किया गया पेपर है जिसमें कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट की विलय करने के क्लेम, 10-40 सेकेंड/100 एमएम की गरली पोरसिटी और 6-12 एन/15 एमएम का वेट टेसाइल क्षमता है और जिसमें फीलर के रूप में टाइटेनियम डाई ऑक्साइड अथवा पिगमेंट" (जिसे यहां आगे "डेकोर पेपर" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) है। यह उच्च दबाव (एचपीएल) अथवा निम्न दबाव (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट्स के लिए बेस पेपर है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च दबाव अथवा निम्न दबाव के लेमिनेट के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर परंतु जिसमें उपयोग करने के लिए तैयार प्रिंटेड डेकोर पेपर शामिल नहीं है, के रूप में भी जाना जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर जैसे सर्फेसिंग पेपर (व्हाइट/ऑफ व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ व्हाइट), बेरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (क्लर/व्हाइट) शामिल हैं। इसका आयात वेक्सीन, कोटिंग और इम्प्रेगेशन के लिए बेस पेपर; प्रिंटिंग के लिए बेस पेपर; डेकोरेटिव उद्योग में उपयोग किए जाने के लिए बेस पेपर और बेरियर पेपर के रूप में आयात किया जा सकता है और ये विभिन्न आकारों जैसे 95 सीएम, 96 सीएम, 102 सीएम, 123 सीएम, 123.5 सीएम, 124 सीएम, 124.5 सीएम, 125 सीएम, 131 सीएम, 132 सीएम, 183 सीएम, 184 सीएम तथा 185 सीएम के रूप में आ सकता है।

5. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन दबाई गई शीट के रूप में पल्प से किया जाता है जो पल्प सस्पेंशन का निर्माण करने के लिए पानी में स्लस होता है ताकि पल्प उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके। इस प्रक्रिया के दारान, फाइबर को अलग किया जाता है। डेकोर पेपर का उत्पादन करने के लिए फाइबरों को यांत्रिक कार्य की कार्रवाई से तथा जलीय माध्यम (जल) की मौजूदगी में परिष्कृत किया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया में एडीटिप्स को मिलाया जाता है जिसका उपयोग सतह में सुधार लाकर प्रिंट की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा अपारदर्शिता, सफेदीपन में सुधार लाने के उद्देश्य से फाइबरों के बीच स्थानों में फिलर के रूप में किया जाता है। उसके बाद अवांछनीय कणों को सफाई के माध्यम से निकाला जाता है। कम किए हुए पल्प सस्पेंशन की मात्रा को आगे सभी संघटकों को सही तरीके से वितरित करने के साथ एक परिष्कृत, चौड़ी और एक समान शीट में परिवर्तित किया जाता है जिसके बाद इस शीट से पानी को निकाला जाता है, सुखाया जाता है और केलेंडर किया जाता है। अंत में इन शीट को आवश्यकता के अनुसार स्लॉट के रूप में बनाया जाता है और उसकी पैकिंग की जाती है।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम 48059100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का भी आयात 48022090 के अंतर्गत किया जा रहा है। दोनों सीमाशुल्क वर्गीकरण पर वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार किया गया है। हालांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. प्रिंटेड डेकोर पेपर डेकोर पेपर का एक रूप है और इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समान वस्तु है।
- ख. मुद्रित डेकोर पेपर को जॉच बाहर करने के पीछे का कारण मान्य नहीं है। मुद्रित डेकोर पेपर पर शुल्क की अनुपस्थिति उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी और हानिकारक होगी, क्योंकि इससे संबद्ध देश से मुद्रित डेकोर पेपर के आयात में वृद्धि हो सकती है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से मुद्रित डेकोर पेपर को बाहर करने के परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन होगा क्योंकि आयातित मुद्रित डेकोर पेपर घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद की तुलना में सस्ता हो जाएगा। संबद्ध देश से आयातित पूर्व-मुद्रित डेकोर पेपर का विवरण मुद्रण को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद के समान है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद 40-90 जीएसएम तक सीमित होना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी वेबसाइट पर उद्धृत इन श्रेणियों के बीच उत्पादन करता है। कोटेड पेपर और न्यूजप्रिंट पर जांच में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा नहीं निर्मित उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा है।
- ङ. याचिकाकर्ता 100 जीएसएम से अधिक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है और इसलिए उस पर पाटनरोधी शुल्क की मांग नहीं कर सकता है। केवल 100 से अधिक जीएसएम का उत्पादन करने की क्षमता पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। 100 जीएसएम से अधिक के उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

- च. चीन जन गण की तुलना में भारत में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड की सफेदी और कम रोशनी प्रतिरोध की दर कम है। चूंकि भारत में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, इसलिए इसे दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- छ. प्राधिकारी को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर को किसी भी रंग पर विचार किए बिना विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसमें सफेद रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर भी शामिल है।
- ज. विचाराधीन उत्पाद दो अलग-अलग प्रकार के पेपर हैं, एक सीधे लैमिनेटर द्वारा उपयोग किया जाता है और दूसरा प्रिंटर द्वारा उपयोग किया जाता है जो लैमिनेटिंग क्षेत्र के लिए मुद्रित पेपर का निर्माण करता है। लैमिनेटरों द्वारा सीधे उपयोग किए जाने वाले कागजों में विशिष्ट तकनीकी विनिर्देश और गुणवत्ता मापदंड होते हैं और प्रिंटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज की तुलना में लागत और कीमत उच्च होती है। प्रत्येक प्रकार और उप-प्रकार का डेकोर पेपर तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य नहीं है। पेपर निर्माता पहले से तय करते हैं कि लैमिनेटर या प्रिंटर के लिए डेकोर पेपर बनाना है या नहीं। आवेदक ने लैमिनेटरों और प्रिंटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेकोर पेपर की उत्पादन प्रक्रिया के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं किया है।
- झ. आवेदक मुख्य रूप से कम जीएसएम के साथ प्रिंट बेस पेपर का उत्पादन कर रहा है। लैमिनेटिंग उद्योग काफी हद तक आयात पर निर्भर है क्योंकि आवेदक द्वारा लैमिनेट के लिए बेस पेपर का उत्पादन और बिक्री नगण्य है।
- ञ. आवेदक द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पादित और आपूर्ति नहीं किए गए किसी भी प्रकार या उप प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ट. आवेदन को पीसीएन के लिए एक मापदंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह लागत और कीमत को प्रभावित नहीं करता है। निर्यातकों को आवेदन के आधार पर उत्पादों में अंतर करने में कठिनाई होगी क्योंकि उन्हें ग्राहकों के उपयोग का ज्ञान नहीं है।
- ठ. केवल यह बात कि उत्पाद गलत वर्गीकृत है या गलत घोषित किया गया है, शुल्क दायरे में 4802 20 90 को शामिल करने का आधार नहीं हो सकता है। इस कोड को शामिल करने से आयातकों के लिए वास्तव में इस कोड के तहत आने वाले सामानों की निकासी में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
- ड. जॉच से बाहर रखे गए प्रिंटेड डेकोर पेपर में अलग-अलग एचएसएन कोड होते हैं, यानी 48119099, और इसे 'प्री-प्रिंटेड डेकोर पेपर' भी कहा जाता है। यह मैसर्स मैच ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य उपयोगकर्ता/सजावट प्रिंटर द्वारा भी उत्पादित होता है। उक्त उत्पाद को चीन जन गण से भारत में निर्यात भी किया जा रहा है।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद 40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर है, जिसमें कम से कम 12 मिमी प्रति 10 मिनट की क्लेम अवशोषकता, 6-12 एन/15 मिमी की गीली तन्यता और 10-40 सेकंड/100 मिलीलीटर की गर्मी पोरोसिटी और फाइलर के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट होती है। इसे आमतौर पर डेकोर पेपर, डेकोरेटिव बेस पेपर, हाई-प्रेशर या लो-प्रेशर लैमिनेट्स के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में जाना जाता है। इस दायरे में उपयोग के लिए तैयार डेकोर पेपर शामिल नहीं है।
- ख. बाजार की भाषा में, विचाराधीन उत्पाद को वैक्सिंग, कोटिंग और इंफ्रेगेशन के लिए बेस पेपर, प्रिंटिंग के लिए बेस पेपर, सजावटी उद्योग में उपयोग के लिए बेस पेपर, बैरियर पेपर के रूप में परिभाषित किया गया है, और आमतौर पर 95/96/102 सेमी; 123/123.5/124/124.5/125 सेमी; 131/132 सेमी; 183/184/185 सेमी के रील आकार में आता है।
- ग. परिवर्चना से बचने के लिए विचाराधीन उत्पाद का पूरा विवरण शुल्क तालिका में उपयोग किया जाना चाहिए।
- घ. इस तर्क के संबंध में कि मुद्रित रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक ने याचिका में मुद्रित रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर शामिल नहीं किया है क्योंकि वह आवेदक घरेलू उद्योग का गठन नहीं करता है।
- ङ. हितवद्ध पक्षकारों ने टाइटेनियम डाइऑक्साइड सामग्री के आधार पर उत्पाद को बाहर रखने की मांग की पहचान नहीं की है। हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले

टाइटेनियम डाइऑक्साइड 'आयातित 100% रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसमें 99% शुद्धता है' और आवेदक द्वारा उत्पादित डेकोर पेपर की गुणवत्ता चीन जन गण से आयातित उत्पाद की तुलना में बेहतर है। प्रयोगशाला रिपोर्टें दर्शाती हैं कि घरेलू सामानों की लैमिनेट अस्पष्टता आयातित माल से तुलनीय है।

- च. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को "रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर, को रंग पर विचार किए बिना विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है" का उल्लेख करना चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि केवल इसलिए कि कुछ उपभोक्ता कागज को प्रिंट करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आवेदक का उत्पाद उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए, इसे दायरे में शामिल किया गया है।
- छ. चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, इसलिए उचित तुलना के लिए पीसीएन वार विश्लेषण महत्वपूर्ण है। पीसीएन जीएसएम, रंग और अनुप्रयोग पर आधारित होने चाहिए।
- ज. हितवद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आवेदन को पीसीएन के लिए एक मापदंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सरफेसिंग या लाइनर के लिए उपयोग की जाने वाली संबद्ध वस्तुएँ दूसरों से भिन्न होती हैं और उच्च टाइटेनियम डाइऑक्साइड और पिगमेंट्स के उपयोग के कारण उच्च लागत और कीमत की होती है।
- झ. घरेलू उद्योग ने प्रिंटरों के साथ-साथ लैमिनेटरों को संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री की है।
- ञ. हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक ने 90 जीएसएम से अधिक संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है और उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि 90 जीएसएम से ऊपर की संबद्ध वस्तु आवेदक की वेबसाइट पर नहीं दिखाई जाती है, अप्रासंगिक है क्योंकि बिक्री, बिक्री प्रतिनिधियों के माध्यम से की जाती है न कि वेबसाइट के माध्यम से।
- ट. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने वाले बीजक संलग्न किए हैं कि उसने 90 जीएसएम से अधिक की संबद्ध वस्तु की बिक्री की है।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई पीसीएन-वार सूचना पहले ही दर्शाती है कि उसने 90 से अधिक जीएसएम की संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री की है।
- ड. संबद्ध वस्तुओं का आयात एचएस कोड 4805 91 00 और 4802 20 90 के तहत किया जा रहा है। हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के विपरीत, एचएस कोड 4802 20 90 के तहत संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का आयात किया जा रहा है। तदनुसार, दोनों कोडों पर विचार किया जाना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में 4802 20 90 के अपवर्जन से पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन होगा।
- ढ. संबद्ध वस्तुओं का सामान्यतः उत्पादन और बिक्री वजन के संदर्भ में की जाती है, जो आम तौर पर किग्रा. या एमटी में होता है।
- ण. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित उत्पादों के समान वस्तु है।
- त. हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पूर्व-मुद्रित डेकोर पेपर पर शुल्क न लगाने से परिवर्चना होगी, यह अनुरोध किया जाता है कि परिवर्चना के डर से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि परिवर्चना होती है तो हितवद्ध पक्षकार प्राधिकारी के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. विचाराधीन उत्पाद 40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर है, जिसमें कम से कम 12 मिमी प्रति 10 मिनट की क्लेम अवशोषण क्षमता, 6-12 ए / 15 मिमी की गीली तन्यता मजबूती और 10-40/100 मिली सेकेंड की गुरली पोरसिटी और टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिलर के रूप में पिगमेंट युक्त है। यह उच्च दबाव (एचपीएल) या कम दबाव (एलपीएल) के आधार पेपर है, जिन्हें, उच्च दबाव या कम दबाव वाले लैमिनेट्स सजावटी लेमिनेट्स कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में भी जाना जाता है के सजावटी आधार कागज है, लेकिन इसमें मुद्रित रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर शामिल नहीं है। विभिन्न विवरण जैसे वैक्सिंग, कोटिंग और संसेचन के लिए बेस पेपर, प्रिंटिंग के लिए बेस पेपर, सजावटी उद्योग में उपयोग के लिए बेस पेपर, बैरियर पेपर और विशिष्ट रील आकार 95/96/102 सेमी; 123/ 123.5/124/124.5/125 सेमी; 131/132 सेमी और 183/184/185 सेमी का उपयोग निर्यातकों और आयातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयात के लिए किया गया है।

9. विचाराधीन उत्पाद में लैमिनेट्स के उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला डेकोर पेपर शामिल है जिसमें विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर शामिल हैं, जैसे सरफेसिंग पेपर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंग/सफेद)।
10. डेकोर पेपर को टैरिफ प्रविष्टि 4805 91 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ प्रविष्टि 4802 20 90 के तहत भी आयात किया जाता है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि 4802 20 90 को पाटनरोधी शुल्क लगाने से बाहर रखा जाना चाहिए। चूंकि इस कोड के तहत आयात नगण्य हैं और इससे आयातकों को कठिनाई होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद का एचएस कोड 4802 20 90 के तहत पर्याप्त आयात है। इसलिए, उक्त कोड के अपवर्जन से पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन होगा। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए दोनों कोडों पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
11. कुछ हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा 90 जीएसएम तक सीमित होना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग 90 जीएसएम से अधिक का उत्पादन नहीं करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन-वार सूचना और रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 90 जीएसएम से अधिक के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है और तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 40 - 130 जीएसएम की रेंज की संबद्ध वस्तु शामिल है।
12. कुछ हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि लैमिनेटों द्वारा सीधे उपयोग किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की जाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य के अनुसार घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में और पूरी क्षति अवधि के दौरान लैमिनेटों को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है।
13. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में प्रिंटेड रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर शामिल नहीं है। जबकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इसे उत्पाद के दायरे में शामिल करने की मांग की है, अन्य ने इसका विरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रिंटेड रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर शामिल नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग उस पर शुल्क लगाने की मांग नहीं कर रहा है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है।
14. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू स्तर पर विनिर्मित और भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद में प्रयुक्त टाइटेनियम डाइऑक्साइड में अंतर है। तथापि, घरेलू उद्योग ने बताया है कि वह 99% शुद्धता वाले 100% रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड का आयात करता है, जिसके कारण इसकी गुणवत्ता आयातित वस्तुओं के बराबर है। घरेलू उद्योग ने यह दिखाते हुए परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है कि उसके उत्पादों की लैमिनेट अपारदर्शिता चीन जनवादी गणराज्य से आयातित माल से तुलनीय है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने उस उत्पाद को परिभाषित नहीं किया है जिसके लिए अपवर्जन की मांग स्पष्ट रूप से की गई है। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने आयातित माल के लिए समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया है। तदनुसार, इस संबंध में उत्पाद के दायरे में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
15. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पीसीएन पद्धति पर विचार किया है :-

क्र.सं.	विशेषताएं	कोड विवरण	कोड संकेत
1	जीएसएम	50 से कम जीएसएम	"1"
		50 जीएसएम से 70 जीएसएम तक	"2"
		70 जीएसएम और उससे अधिक	"3"
2	कलर	कलर्ड डेकोर पेपर	"सी"
		अनकलर्ड डेकोर पेपर	"यू"
3	अनुप्रयोग	लाइनर/सरफेसिंग अनुप्रयोग के लिए डेकोर पेपर	"1"
		अन्य अनुप्रयोगों के लिए डेकोर पेपर	"2"

16. प्राधिकारी के पास रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों के विचार

17. घरेलू उद्योग और इसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. आईटीसी ने स्वीकार किया कि उसने 2017-18 के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था लेकिन आवेदन में संलग्न आयातों की घोषणा और विवरण में उस अवधि का उल्लेख नहीं है जिसके दौरान उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था। प्राधिकारी को इसे सत्यापित करना चाहिए और इसका खुलासा करना चाहिए।
- ख. आवेदक ने दावा किया कि श्री कृष्णा पेपर्स ने आवेदन का समर्थन किया है। तथापि, कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी अन्य निर्माता ने आवेदन का समर्थन नहीं किया है।
- ग. मौखिक सुनवाई से पहले आवेदक ने यह खुलासा नहीं किया कि श्री कृष्णा पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड याचिका का समर्थन कर रहा है।
- घ. यदि श्री कृष्णा पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड याचिका का समर्थन कर रहा है, तो उसे अपनी क्षति की जानकारी भी देनी चाहिए।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदन आईटीसी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। उसने जांच की अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित नहीं है।
- ख. आवेदक ने अपने संयंत्र के बंद होने के कारण 2017-18 में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया था।
- ग. इसके प्लांट और मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए 2017-18 में आवेदक के संयंत्र को करीब सात महीने के लिए बंद कर दिया गया था। तदनुसार, अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए, आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया।
- घ. आवेदक के पास भारत में घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक नामतः पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं।
- ड. श्री कृष्णा पेपर्स ने जाँच शुरूआत के बाद एक समर्थन पत्र दायर किया है। किसी भी मामले में, आवेदक के पास अकेले घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और इस तरह के समर्थन के बिना भी घरेलू उद्योग का गठन करता है।
- च. इस तर्क के संबंध में कि श्री कृष्णा पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्षति की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, यह अनुरोध किया गया था कि आवेदक किसी भी निर्माता को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी अन्य उत्पादक के समर्थन के बिना भी, आवेदक के पास भारत में उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

20. आवेदन आईटीसी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। यह नोट किया जाता है कि आईटीसी लिमिटेड ने 2017-18 में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है लेकिन उस वर्ष कुल आयात का केवल *** था। तथापि, जांच की अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किया गया है। आगे यह नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी ने पाया है कि उत्पादक घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल होने का पात्र है।
21. मौखिक सुनवाई के बाद, श्री कृष्णा पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जून, 2021 में क्षमता, उत्पादन और बिक्री के विवरण के साथ एक पत्र दायर किया है, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का समर्थन किया गया है। तथापि, उन्होंने क्षति की सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए, उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
22. आवेदक के पास घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।

उत्पादक	उत्पादन (एमटी)	उत्पादन में हिस्सा (%)	उत्पादन में हिस्सा (रैंज)
आईटीसी लि.	***	***	70-80
पुदुमजी पेपर प्रॉडक्ट्स लि.	***	***	10-20
श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.	***	***	5-15
कुल भारतीय उत्पादन	24,227	100%	100%

23. इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईटीसी लि. नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

इ गोपनीयता

इ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. आवेदक और अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन हिस्से को साझा नहीं किया गया है। याचिका में उत्पादन के मूल्य और मात्रा तथा घरेलू उत्पादकों के हिस्से की घोषणा नहीं की गई है। प्राधिकारी ने जिस आधार पर स्थिति संबंधी निर्णय लिया है, वह स्पष्ट नहीं है।
- ख. आवेदक ने आयात के संबंध में उत्पादन और खपत, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, निर्यात बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता आदि के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ग. स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में निर्णय के अनुसार किसी भी डेटा को स्वतः रूप से गोपनीय नहीं रखा जा सकता है। प्राधिकारी को एचआर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में विहित गोपनीयता के दावे का मूल्यांकन करना चाहिए।
- घ. कच्चे माल के नाम, विनिर्माण प्रक्रिया, कुल मात्रा का स्रोत और भारतीय उत्पादन का मूल्य और क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानदंडों का स्रोत, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना और कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी की सीमा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जुटाई गई धनराशि के लिए, वित्तीय विवरणों का संदर्भ दिया गया है जो अनुपलब्ध हैं।
- ड. प्रत्येक उत्पाद प्रकार द्वारा कवर किए गए आयातों का कुल प्रतिशत और प्रत्येक उत्पाद प्रकार के लिए कीमत में कटौती का खुलासा नहीं किया गया है।
- च. आवेदक ने उस कुल अवधि का खुलासा नहीं किया है जिसके लिए संयंत्र चालू नहीं था, आईटीसी द्वारा आयात की वास्तविक मात्रा, विचाराधीन उत्पाद के आयात का कारण और किस आधार पर आकड़ों में समायोजन किया गया था, को नहीं बताया गया है।

- छ. आवेदक ने अगोपनीय याचिका में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराकर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिका के खंड VI के लिए, प्रारूप ए से एल के लिए एक संदर्भ रखा गया है लेकिन कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। प्रदान की गई औचित्य तालिका व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है।
- ज. व्यापार नोटिस में आवश्यक के रूप में क्षतिरहित कीमत $\pm 10\%$ की सीमा में प्रदान नहीं की गई है।
- झ. खरीद नीति, बिक्री नीति, लेखा नीति, लागत लेखा नीति और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के गोपनीय होने का दावा किया गया है। उपयोगिता खपत, उत्पादन की लागत, कच्चे माल और पैकिंग सामग्री की खपत के संबंध में जानकारी की प्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है।
- ञ. प्राधिकारी को आवेदक को हितवद्ध पक्षकारों को लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश देना चाहिए।

इ.2. घरेलू उद्योग के विचार

25. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. उत्पादकों/निर्यातकों ने सार्वजनिक डोमेन में दी गई जानकारी को गोपनीय बताते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. उत्पादकों/निर्यातकों ने ट्रेड नोटिस 10/2018 और 01/2013 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है।
- ग. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, आवेदक ने कुल उत्पादन में अपना हिस्सा प्राधिकारी के साथ साझा किया है और प्राधिकारी ने इसकी जांच की है जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना से स्पष्ट है। चूंकि बाजार में केवल तीन उत्पादक हैं, इस तरह की जानकारी का एक सीमा में भी प्रकटीकरण अन्य घरेलू उत्पादकों को उत्पादन का अनुमान प्रदान कर देगा। आवेदक ने समग्र आधार पर सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी प्रदान करके ट्रेड नोटिस 10/2018 के तहत अपने दायित्व को पूरा किया है।
- घ. कुल उत्पादन में आवेदक की हिस्सेदारी, बंद रहने की अवधि, आवेदक द्वारा आयात की मात्रा, उत्पादन और खपत के संबंध में आयात, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण, स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, निर्यात बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता आदि के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा मांगी गई सूचना गोपनीय प्रकृति की है। हितवद्ध पक्षकारों ने स्वयं अपने उत्तर में ऐसी सूचना का खुलासा नहीं किया है।
- ङ. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, आवेदक ने याचिका में प्रमुख कच्चे माल के नाम, निर्माण प्रक्रिया, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का खुलासा किया है। परिकलित सामान्य मूल्य व्यापार संवेदनशील जानकारी पर आधारित है और केवल परिकलित सामान्य मूल्य की रेंज को साझा किया गया है। आवेदक के वित्तीय विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और उसी के लिए लिंक साझा किया गया था। औसत उद्योग मानदंडों के लिए कोई स्रोत नहीं है क्योंकि यह आवेदक की बाजार आसूचना जानकारी पर आधारित है।
- च. इस तर्क के संबंध में कि शटडाउन अवधि के समायोजन के लिए कार्यप्रणाली को साझा नहीं किया गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक ने लागत के अनुकूलन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति का पालन किया है। इसने अपने उत्पादन और उत्पादन की लागत को इस तरह निर्धारित किया है जैसे कि संयंत्र बंद नहीं हुआ था और उच्च उत्पादन मात्रा पर स्थिर लागत आवंटित की थी।
- छ. हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक ने व्यापार सूचना की आवश्यकताओं के अनुसार औचित्य तालिका प्रदान की है।
- ज. लागत प्रारूपों की प्रवृत्तियों और आवेदक की नीतियों के संबंध में, सूचना व्यवसाय के स्वामित्व वाली प्रकृति की है और इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि हितवद्ध पक्षकारों ने भी ऐसी सूचना का खुलासा नहीं किया है। हितवद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।
- झ. इस तर्क के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत $\pm 10\%$ की रेंज में प्रदान नहीं की गई है, यह अनुरोध किया जाता है कि क्षतिरहित कीमत के प्रकटीकरण के रूप में एक व्यापक श्रेणी साझा की गई है जिससे ग्राहक अपनी कीमतों को बेंचमार्क कर सकेंगे और आवेदक से कीमत कम करने की मांग करेंगे।
- ञ. आवेदक ने सौदा-वार सूची संलग्न की है और हितवद्ध पक्षकार प्राधिकारी को आवश्यक वचनबद्धता देकर इसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इ. 3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

27. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटन एक प्रतियोगी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन का सूचना की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की, पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), अथवा जो किसी जांच के लिए पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है, अच्छे कारण बताए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा ऐसा माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना वह सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

28. प्राधिकारी ने आवेदक और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता पर दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को, अनुरोध किए जाने पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए।

29. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन में अपने हिस्से, उत्पादन और खपत के संबंध में आयात, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, निर्यात बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता, शटडाउन की अवधि, किए गए आयात की मात्रा, प्रारूप ए से एल, क्षतिरहित कीमत, खरीद नीति, बिक्री नीति, लेखांकन नीति, लागत लेखांकन नीति, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं, उपयोगिता खपत, उत्पादन की लागत, कच्चे माल और पैकिंग सामग्री की खपत का खुलासा नहीं किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना गोपनीय प्रकृति की होती है और इसलिए इसका प्रकटीकरण घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों के प्रतिकूल होगा। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इसी तरह की सूचना के संबंध में संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के गोपनीयता के दावों को भी स्वीकार कर लिया है।

30. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने कच्चे माल के नाम, विनिर्माण प्रक्रिया, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना और संयंत्र बंद होने के कारणों का खुलासा किया है। जहां तक जुटाई गई निधियों का संबंध है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए उसकी अलग से पहचान नहीं की जा सकती है।

31. डीजीसीआईएंडएस आकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आकड़ों को भारत में निर्यातक देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य से संबंधित हितबद्ध पक्षों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, आवेदक ने लेनदेन के अनुसार आयात आकड़ों की पूरी सूची प्रदान की है। यह भी नोट किया जाता है कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से स्वतंत्र रूप से आकड़ों को प्राप्त कर सकता है और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपना स्वयं का प्रति दावा दायर कर सकता है। प्राधिकारी का मानना है कि आयात आकड़ों को साझा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया 15 मार्च 2018 के व्यापार सूचना 07/2018 में निर्धारित की गई है। यह प्रावधान करता है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए चयनित आयात आकड़ों को हार्ड कॉपी में साझा किया जा सकता है और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से आयात लेनदेन आकड़ों द्वारा अपरिष्कृत लेनदेन की मांग करने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार की मांग कर सकते हैं। क्रमबद्ध आयात आकड़ों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा/वचनबद्धता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ बनाया गया था। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू की जा रही प्रक्रिया सुसंगत, सभी पक्षों और जांचों में एक समान है और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

च. विविध मुद्दे**च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

32. अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं:

क. जांच शुरू करने की अधिसूचना के पैरा 15 में कहा गया है कि प्राधिकारी के पास पाटन और क्षति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य था। तथापि, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य "पर्याप्त साक्ष्य" होने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाले होने चाहिए, न कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य। मेक्सिको - पाइप्स एंड ट्यूब्स में पैनल ने नोट किया कि पर्याप्तता का निर्धारण सटीकता और साक्ष्य की पर्याप्तता के आकलन पर आधारित होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका - कनाडा से सॉफ्टवुड लम्बर के विवाद में पैनल ने माना कि पर्याप्तता का मतलब केवल आरोपों या अनुमान से अधिक है। ग्वाटेमाला - सीमेंट II में, पैनल ने नोट किया कि केवल पाटन, क्षति और कारण के पर्याप्त साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। जांच एजेंसी को साक्ष्यों की सटीकता और पर्याप्तता से खुद को संतुष्ट करना चाहिए था।

ख. याचिका तथ्यों को छिपाने और गलत तरीके से पेश करने पर आधारित है, और प्राधिकारी ने याचिका की पर्याप्तता और सटीकता की जांच करके प्रथम दृष्टया मामले से खुद को संतुष्ट नहीं किया।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

33. अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथा वर्णित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया से स्वयं को संतुष्ट किया। हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक द्वारा गलत प्रकटन के किसी भी उदाहरण पर ध्यान नहीं दिलाया है।

ख. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, शुरूआत के चरण में केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता होती है जैसा कि राजस्थान में उच्च न्यायालय द्वारा टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटनरोधी महानिदेशक मामले में माना गया था। और हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में और ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा माना गया था।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने एक विधिवत रूप से प्रमाणित आवेदन प्रदान किया है, जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी। वर्तमान जांच प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/सूचना के आधार पर और इस बात से स्वयं को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने के बाद कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, शुरू की गई थी। इसके अलावा, जांच शुरू करने के बाद, आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक जानकारी मांगी गई है और वह आवेदक द्वारा प्रदान की गई है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

क. चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की परिपाटी 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई थी।

ख. भारतीय प्राधिकारी को इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की गणना में प्रतिनिधि देश पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहिए, भले ही चीन जन गण को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश न माना जाए।

ग. यूरोपीय संघ के विरुद्ध फास्टर मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट ने मजबूत औचित्य प्रदान किया है कि चीन जन गण को स्वचालित रूप से बाजार-अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

घ. "संधि का सद्भाव" के सिद्धांतों का पालन करते हुए, भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत चीन जन गण को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता देने के लिए बाध्य है। चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि 11 दिसंबर, 2016 के बाद कोई भी देश चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं मान सकता है। भारत के पास अन्यथा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

- ड. कुछ समय पहले तक, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी यह सहमति साझा की थी कि प्रोटोकॉल के 15 साल की समाप्ति के बाद चीन जन गण को एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाएगा।
- च. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आर्थिक विकास के स्तर और बाजार की स्थितियों के संदर्भ में यूरोपीय संघ की तुलना चीन जन गण से नहीं की जा सकती है। दोनों बाजारों में डेकोर पेपर के प्रकार, उनकी कीमत और गुणवत्ता की तुलना की जानी चाहिए। कुइदुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुसार, बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के आर्थिक विकास का स्तर उन मामलों में प्रासंगिक है जहां सामान्य मूल्य ऐसे देश में भुगतान या देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- छ. यूरोपीय संघ सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त तीसरा देश नहीं है क्योंकि इसकी विनिर्माण, श्रम, अनुपालन लागत और प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन जन गण की तुलना में बहुत अधिक है।
- ज. नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का चयन करते समय विकास के स्तर पर विचार किया जाएगा। यदि इसकी अवहेलना की जाती है, तो यह कु. सोनिया भाटिया बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य मामले में निर्णय से असंगत होगा, जिसमें यह माना गया था कि विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए गए हर एक शब्द को महत्व दिया जाना चाहिए।
- झ. ग्लुनवल्ड लॉजिस्टिक सर्विस जीएमबीएच बनाम हाउपजोलेस्ट हैमबर्ग-स्टैंडर्ट मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय ने कहा कि बाजार अर्थव्यवस्था उसे माना जाना चाहिए जिसमें उत्पाद की कीमत निर्यात के देश में समान परिस्थितियों में बनती है।
- ञ. यूरोपीय संघ से भारत में आयात चीन जन गण से आयात से कम है।
- ट. घरेलू उद्योग ने यह नहीं बताया है कि यूरोपीय संघ से निर्यात किए गए पीसीएन की तुलना चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात किए गए पीसीएन से कैसे की जा सकती है।
- ठ. यूरोपीय संघ से आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक हैं और यूरोपीय संघ में उत्पादन की लागत अधिक है।
- ड. यूरोपीय संघ चीन के उत्पादकों की तुलना में शेड्स और रंगों की उच्च श्रेणी प्रदान करता है।
- ढ. सामान्य मान का निर्माण निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है:
 - i. लागत के निर्माण के लिए कच्चे माल की खपत मानदंड।
 - ii. कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत पर विचार किया जा सकता है।
 - iii. चीन जन गण में कीमतों के आधार पर उपयोगिता लागत को ज्ञात किया जा सकता है।
 - iv. चीन जन गण सहित अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर विचार किया जा सकता है।
- ण. अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार, विचार किया जाने वाला परिकलित सामान्य मूल्य तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत है, न कि केवल एक देश को निर्यात कीमत। इसलिए, किसी तीसरे देश से औसत निर्यात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए।
- त. आवेदक ने मौखिक सुनवाई के दौरान तीसरे देश में कीमत से सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पद्धति को तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत में बदलने का प्रयास किया। हितवद्ध पक्षकारों को नोटिस दिए बिना और उनकी टिप्पणियां मांगे बिना इस तरह के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- थ. संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली की धारा 9(1)(ग) और अनुबंध 1 का उल्लंघन करता है और निर्यात कीमत के संबंध में किया गया समायोजन असामान्य रूप से अधिक है। जांच शुरू करने से पहले प्राधिकारी को साक्ष्य में ऐसी कमी पर विचार करने की आवश्यकता थी।
- द. निवल निर्यात कीमत के समायोजन के लिए याचिका में प्रस्तुत आंकड़े केवल निराधार दावे हैं और जांच की शुरुआत के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य को बढ़ा दिया है और निर्यात कीमत को कम कर दिया है, जो पाटन का पता लगाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
- ध. घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यूरोपीय संघ द्वारा भारत को निर्यात किए गए पीसीएन की तुलना चीन जन गण द्वारा भारत को निर्यात किए गए पीसीएन से कैसे की जा सकती है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

36. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन जन गण को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. 11 दिसंबर, 2016 को, चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के केवल अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधान समाप्त हो गए, लेकिन अनुच्छेद 15 (क) (i) लागू रहे, जिसके लिए उत्पादकों को यह दर्शाना होगा कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। प्राधिकारी ने हाल की सभी जांचों में चीन जन गण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है जब तक कि निर्यातक/उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन काम कर रहे हैं।
- ग. ईसी-फास्टनरों में, अपीलीय निकाय के समक्ष मुद्दा विशेष रूप से नहीं था, कि क्या अनुच्छेद 15 (क) या केवल अनुच्छेद 15 (क) (ii) के पूरे प्रावधान 15 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएंगे और इस प्रकार, उस पर निर्भरता उचित नहीं है। इसलिए, चीन जन गण विकृतियों को दूर करने और बाजार द्वारा कीमत निर्धारित करने की अनुमति देने के अपने दायित्व में विफल रहा है।
- घ. अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित अन्य विश्व व्यापार संगठन के देश भी चीन जन गण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानते हैं।
- ङ. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुरूप है।
- च. चूंकि किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए अनुरोध नहीं किया है, इसलिए उन्हें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालन के रूप में माना जाना चाहिए। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में यूरोपीय संघ के आयातों के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि यूरोपीय संघ का चीन जन गण के बाद संबद्ध वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन और खपत है।
- छ. हितवद्ध पक्षकारों ने इस तर्क के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिनिधि देश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून प्रतिनिधि देश पद्धति को प्राथमिकता प्रदान करता है।
- ज. इस तर्क के संबंध में कि अनुबंध I पैरा 7 में एक देश का उल्लेख नहीं है लेकिन अन्य देशों का उल्लेख है और यदि "या" का उल्लेख किया गया होता भारत में कीमत पर विचार किया जा सकता था, यह अनुरोध किया जाता है कि धारा 9 क(1)(ग) प्राधिकारी को "होगा" शब्द के उपयोग से एक अधिदेश प्रदान करता है। तथापि, अनुबंध-I के पैरा 7 के अधीन ऐसा कोई अधिदेश नहीं दिया गया है। इसके तहत निर्दिष्ट सभी विधियां केवल एक देश को संदर्भित करती हैं। यदि ऐसे देश से दूसरे देशों को निर्यात की कीमत की व्याख्या इस तरह से की जाती है कि इसमें सभी देश शामिल हों, तो यह प्राधिकारी के लिए एक बड़ी प्रक्रिया होगी। किसी भी मामले में, यूरोपीय संघ से आयात की कीमत वास्तव में भारत में भुगतान की गई कीमत है।
- झ. हितवद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि विकास के स्तर के कारण यूरोपीय संघ को एक प्रतिनिधि देश के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए, गलत है क्योंकि विकास का स्तर एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से भारत में निर्यात के मामले में अप्रासंगिक है और केवल प्रतिनिधि देश में प्रक्रिया के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करते समय प्रासंगिक हो जाता है, जैसा कि कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी बनाम निर्दिष्ट प्राधिकरण में न्यायाधिकरण द्वारा माना गया था। केवल निर्यात की मात्रा और क्या जांच की अवधि के दौरान देश पाटन कर रहा है, प्रासंगिक है।
- ञ. इस तर्क पर कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त सभी शब्दों को महत्व दिया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने माना है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित मूल्य का निर्धारण करते समय विकास का स्तर प्रासंगिक है, लेकिन आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत को निर्यात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।
- ट. इस तर्क के संबंध में कि यूरोपीय संघ में लागत अधिक है और निर्यात कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक है, यह अनुरोध किया जाता है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था में लागत गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक होगी। क्षतिरहित कीमत और निर्यातकों की लागतों की तुलना करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि लागत + लाभ के आधार पर कोई उपभोक्ता खरीद नहीं करता है। किसी भी मामले में, यदि सामान्य मूल्य क्षति रहित कीमत से अधिक है, तो शुल्क को क्षति मार्जिन स्तरों तक सीमित रखा जाएगा।
- ठ. शेडों और रंगों की तुलना के संबंध में, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार विश्लेषण किया है जिसमें हितवद्ध पक्षों की टिप्पणियों के बाद पीसीएन का निर्णय लिया गया था।

- ड. इस तर्क के संबंध में कि यूरोपीय संघ से आयात कुल आयातों का 10% है और इसकी कीमत अधिक है, यह अनुरोध किया जाता है कि यूरोपीय संघ चीन जन गण वाद संबद्ध वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है। कीमत अंतर गैर-तुलनीयता का संकेत नहीं देता है क्योंकि ज्यादातर मामलों में किसी प्रतिनिधि देश से आयात की कीमत संबद्ध देश से अधिक या कम होती है।
- ढ. यूरोपीय संघ में कीमतों के संबंध में सूचना के अभाव में, आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत को निर्यात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। वैकल्पिक रूप से, भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य उपलब्ध कराया गया है।
- ण. हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के बारे में कि यूरोपीय संघ को एक प्रतिनिधि देश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यूरोपीय न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे का फैसला किया है और यूरोपीय न्यायालय के फैसले को इसकी तुलना में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।
- त. हितवद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आवेदक ने मौखिक सुनवाई के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली को बदलने का प्रयास किया, गलत है क्योंकि आवेदक ने याचिका में कहा है कि सामान्य मूल्य का परिकलन भारत को यूरोपीय संघ से निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- थ. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत को निर्यात की कीमतों का साक्ष्य प्रदान किया है।
- द. यद्यपि प्राधिकारी सामान्य मूल्य का परिकलन करने का निर्णय लेते भी हैं, तब भी चीन जन गण में सुविधाओं की लागत और व्याज दरों पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे विकृत हैं और निर्यातक यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में काम कर रहे हैं।
- ध. निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस से एकत्र किए गए आयात आंकड़ों के आधार पर निकाली गई है और निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा व्यय के लिए समायोजन किए गए हैं।
- न. निर्यात कीमत के लिए समायोजन प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार हैं।
- प. जियानहे डेकोरेटिव वेस पेपर का निर्माता है जैसा कि इसकी वेबसाइट पर बताया गया है। तथापि, इसने सूचना एक उत्पादक के रूप में नहीं बल्कि केवल एक निर्यातक के रूप में प्रदान की है।
- फ. जियानहे ने बताया है कि यह विशेष पेपर तैयार करता है। विचाराधीन उत्पाद भी एक विशिष्ट कागज है और कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध वस्तु से किस प्रकार भिन्न है, इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- ब. जियानहे ने बताया है कि उसका कोई संयुक्त उद्यम नहीं है। तथापि, किंगडेकोर जियानहे और शेटडेकोर एजी का संयुक्त उद्यम है।
- भ. किंगडेकोर की भारत में एक संबंधित इकाई है, जिसका नाम शाह इंटरनेशनल है, जो कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं संबंधी कार्य कर रही है। यदि शाह इंटरनेशनल किंगडेकोर द्वारा उत्पादित माल का आयातक है, तो प्रश्नावली के भाग IV को भरा जाना आवश्यक था। यदि शाह इंटरनेशनल ने बिक्री कार्यालय के रूप में कार्य किया है, तो उसके द्वारा की गई बिक्री और वितरण लागत का मात्रा निर्धारित करने और निर्यात कीमत में समायोजित करने की आवश्यकता है।
- म. मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब और चीन जन गण के मूल के या वहांसे निर्यातित गैर-बुने कपड़े के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में [सं. 14/23/2015-डीजीएडी], प्राधिकारी ने निर्यातकों में से एक की प्रतिक्रिया को इस कारण से खारिज कर दिया कि वह भारत में अपने कार्यालय के अस्तित्व का खुलासा करने में विफल रहा था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए भारत में बिक्री कार्यालय के बिक्री और सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को भी कम करना आवश्यक है।
- य. जियानहे ने अपने प्रत्युत्तर में बताया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए अनुसंधान और विकास, उत्पादन, बिक्री, लाइसेंसिंग, तकनीकी और पेटेंट समझौते से संबंधित किसी अन्य कंपनी के साथ कोई संयुक्त उद्यम नहीं है। तथापि, इसकी सहायक किंगडेकोर (झेजियांग) कं., लि. ("किंगडेकोर") शेटडेकोर एजी के साथ एक संयुक्त उद्यम है।

- र. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के संबंध में सब्सिडी रोधी जांच में अपने पिछले जाँच परिणामों में लगातार पाया है कि चीन जन गण में उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य से कम पर पानी और बिजली सहित अधिमानी ऋण और सुविधाओं तक पहुंच से लाभ मिलता है। इसलिए, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ऐसी दरों पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- ल. क्षतिरहित कीमत और निर्यातकों की लागत की तुलना अप्रासंगिक है, क्योंकि कोई भी आयातक/उपभोक्ता निर्यातक की लागत के आधार पर निर्यातकों को कीमत का भुगतान नहीं करता है।
- व. ऐसा कोई कानून नहीं है कि सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत अधिक नहीं हो सकता है। भले ही सामान्य मूल्य क्षति रहित कीमत से अधिक हो, शुल्क को क्षति मार्जिन तक सीमित रखा जाएगा।
- श. यूरोपीय संघ से आयात कुल आयात का 10% है। ये आयात चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की मात्रा के 5% से अधिक हैं और इसलिए, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था

की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में यथा उल्लिखित मान्यता के खंडन के लिए पूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी जो निम्नलिखित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबद्ध पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाना चाहिए, तथापि न तो आवेदक और न ही अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण को संभव बनाने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य प्रदान किए हैं। बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य। प्राधिकारी ने तदनुसार जांच की कि क्या सामान्य मूल्य का निर्धारण ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जा सकता है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि संबंधित टैरिफ कोड के तहत निर्यात के संबंध में आकड़े उपलब्ध हैं, और इसके अलावा भले ही डीजीसीआईएंडएस के आकड़े यूरोपीय संघ से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात की पहचान करना संभव बनाता है, तो भी प्राधिकारी जीएसएम, रंग और अनुप्रयोग के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन प्रणाली को अपनाया है। यूरोपीय संघ से आयात सौदों का विवरण सभी मामलों में जीएसएम, रंग और अनुप्रयोग के आधार पर पीसीएन की पहचान को संभव नहीं बनाता है। इसलिए, पीसीएन-वार जानकारी की सटीक पहचान के अभाव में, सामान्य मूल्य का निर्धारण यूरोपीय संघ से भारत सहित अन्य देशों में आयात के आधार पर नहीं किया जा सकता है।
41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चीन जन गण से भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य "अन्य उचित आधार पर" निर्धारित किया जाता है। विक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन के लिए उचित वृद्धि के बाद घरेलू उद्योग के लिए अनुकूलित उत्पादन लागत पर विचार किया गया है। तदनुसार, जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन जनवादी गणराज्य में सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

42. चीन जनवादी गणराज्य के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

i. किंगडेकोर (जेजियांग) कं., लि.

- ii. जियानहे कं., लि.
- iii. झेजियांग जियानहे न्यू मैटेरियल्स सेल्स कं., लि.
- iv. शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं., लि.
- v. ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि.
- vi. किफेंग न्यू मैटेरियल लि., चीन जन गण

किंगडेकोर (झेजियांग) कं., लि., जियानहे कं., लि., और झेजियांग जियानहे न्यू मैटेरियल्स सेल्स कं., लि., के लिए निर्यात कीमत

निर्यात कीमत

43. किंगडेकोर (झेजियांग) कं., लि., एक सीमित देयता कंपनी (एक संयुक्त उद्यम एंटरप्राइज) है। किंगडेकोर का कानूनी दर्जा पिछले तीन वर्षों में नहीं बदला है। जांच की अवधि के दौरान, किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लि., ने भारत को *** एमटी पीयूसी का सीधे और दो अलग-अलग संबंधित व्यापारियों, जियानहे कं., लि. और झेजियांग जियानहे न्यू मैटेरियल्स सेल्स कं. लि., चीन जन गण के माध्यम से *** एमटी का निर्यात किया है।
44. किंगडेकोर (झेजियांग) कं., लि. ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों, ऋण लागत और बैंक शुल्क के लिए समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लि. के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं., लि., ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि. और क्यूफेंग न्यू मैटेरियल लि. के लिए निर्यात कीमत

45. मेसर्स शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं., लि. ("ओहुआ"), मेसर्स ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि. ("ओउमू") और मेसर्स किफेंग न्यू मैटेरियल लि. ("किफेंग") चीन जन गण. के कंपनी कानून के तहत शेयरों द्वारा सीमित देयता कंपनियां हैं।
46. ओहुआ और ओउमू चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं। ओउमू ने संबद्ध वस्तुओं का सीधे असंबंधित भारतीय ग्राहकों को निर्यात किया है और ओहुआ ने ओउमू और किफेंग के माध्यम से असंबंधित भारतीय ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। ओउमू और किफेंग ने भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात का पीसीएन वार विवरण दिया है। तीनों कंपनियों ने सभी प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित प्रारूपों में प्रदान की थी।
47. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, ओउमू ने भारत में असंबंधित ग्राहक को *** एमटी स्व-उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और *** एमटी ओहुआ द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। किफेंग ने भारत में असंबंधित ग्राहक को ओहुआ द्वारा उत्पादित *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। ओउमू और किफेंग ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। ओहुआ ने पूर्ण-कार्य आधार पर ओउमू और किफेंग को संबद्ध वस्तुओं के बीजक बनाए हैं। प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों के पीसीएन वार ब्यौरों का सत्यापन किया है। यथा निर्धारित भारित औसत पीसीएन वार कारखाना द्वार निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन जन. गण. से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए

48. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

49. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:-

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	पीसीएन	सामान्य मूल्य (रु./एमटी)	निर्यात कीमत (रु./एमटी)	पाटन मार्जिन (रु./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडा./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रैंज)
		चीन जन. गण.						
1)	किंगडेकोर (झेजियांग) कं., लि.	1सी2	***	***	***	***	***	30-40
		2सी1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0)-(10)
		2सी2	***	***	***	***	***	30-40
		2यू1	***	***	***	***	***	10-20
		2यू2	***	***	***	***	***	0-10
		3सी1	***	***	***	***	***	10-20
		3सी2	***	***	***	***	***	0-10
		3यू1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0)-(10)
		3यू2	***	***	***	***	***	0-10
	कुल भारत औसत		***	***	***	***	***	0-10
2)	शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं., लि.	3सी1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0)-(10)
3)	ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि.	2सी1	***	***	***	***	***	0-10
		2यू1	***	***	***	***	***	10-20
		3सी1	***	***	(***)	(***)	(***)	(20)-(30)
		3यू1	***	***	***	***	***	0-10
	कुल भारत औसत (शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं., लि. और ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि.)		***	***	***	***	***	0-10
4)	असहयोगी/अवशिष्ट निर्यातक		***	***	***	***	***	30-40

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

50. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. क्षति अवधि के दौरान मांग और संबद्ध आयात दोनों में वृद्धि हुई है। संयंत्र के बंद होने और क्षमता विस्तार के बाद भी मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।
- ख. आवेदक ने प्राधिकारी को गुमराह किया है क्योंकि उसने मौखिक सुनवाई में अनुरोध किया है कि कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है परंतु याचिका में मात्रात्मक क्षति का दावा किया गया है।
- ग. क्षति अवधि के दौरान पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में गिरावट सामान्य लागत और कीमत प्रवृत्तियों के अनुरूप है जैसा कि घरेलू उद्योग के आंकड़ों से देखा जा सकता है।
- घ. समग्र मूल्य कटौती नकारात्मक थी।

- ड. कुछ उत्पाद प्रकारों के आधार पर घरेलू उद्योग का कीमत कटौती का दावा निराधार है।
- च. घरेलू उद्योग ने द्वितीयक स्रोत के आधार पर विकृत किए गए आकड़े प्रदान किए हैं, अर्थात्, वह आकड़े जिसे उद्योग रखता है, तथा जिसे सकारात्मक कीमत कटौती दिखाने के लिए गोपनीय रखा गया है।
- छ. यह केवल उन प्रकारों को दर्शाना है जो कीमत कटौती प्रदर्शित करते हैं और पाटनरोधी कानूनों के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
- ज. याचिकाकर्ता के पास कीमत बढ़ाने की छूट है, लेकिन क्षमता नहीं होने, कागज की गुणवत्ता, शेड भिन्नता की समस्या, लुगदी भिन्नता, पिन होल्स, ब्लैक स्पॉट, छोटे बैच बनाने में असमर्थता आदि न होने के कारण बेहतर ग्रेड के कागज को बेचने में असमर्थता के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है।
- झ. जैसा कि चीन - यूरोपीय संघ से एक्स-रे सुरक्षा निरीक्षण उपकरण पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क में पैनेल द्वारा माना गया था, यदि नकारात्मक कीमत कटौती के मामले में, यह स्पष्ट करते हुए कि घरेलू उद्योग कम से कम पाटित आयातों के स्तर तक अपनी कीमतों में वृद्धि क्यों नहीं कर सका कीमत ह्रास या न्यूनीकरण के ठोस कारणों की अनुपस्थिति में आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ञ. कीमत कटौती के संबंध में याचिका में दी गई जानकारी अपर्याप्त है क्योंकि कीमत कटौती के लिए विचार किए जाने वाले उत्पाद प्रकार निर्धारित पीसीएन के अनुसार नहीं हैं। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर इस प्रकार की कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया गया है और द्वितीयक आंकड़ों पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिया गया है।
- ट. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है। उत्पादन की लागत अतिरिक्त क्षमता पर पूंजीगत व्यय के कारण प्रभावित हुई है और सामान्य स्थिति में उत्पादन की वास्तविक लागत पर पहुंचने के लिए इसे अलग किया जाना चाहिए। उत्पादन की ऐसी लागत यह दर्शाएगी कि कोई मूल्य ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।
- ठ. घरेलू उद्योग की क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग विस्तार के बाद इष्टतम उपयोग पर काम कर रहा है। क्षमता उपयोग में गिरावट नहीं आई है, भले ही क्षमता 2018-19 में दोगुनी से अधिक हो गई थी।
- ड. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि की दर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि की दर से अधिक है।
- ढ. घरेलू उद्योग अपना संपूर्ण उत्पादन बेच रहा है और अपेक्षित क्षमता के बिना कोई अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी संभव नहीं है।
- ण. यद्यपि घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है, मालसूची का विश्लेषण उत्पादन और बिक्री के प्रतिशत के रूप में किया जाना चाहिए। इसका मूल्यांकन क्षमता में वृद्धि के आलोक में किया जाना चाहिए।
- त. उत्पादन और बिक्री के कई दिवसों के रूप में मालसूची में गिरावट आई। ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में, सेस्टेट ने माना था कि बिक्री की मात्रा में वृद्धि की तुलना में, मालसूची का स्तर समान प्रतिशत-वार बना हुआ है और इसे क्षति संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- थ. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता उच्चतम रही थी।
- द. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ध. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में वृद्धि एक असामान्य प्रवृत्ति दर्शाती है क्योंकि यह स्थापित क्षमता में वृद्धि से अधिक बढ़ी है।
- न. औसत नियोजित पूंजी में वृद्धि संस्थापित क्षमता में वृद्धि के अनुपात में नहीं है।
- प. सकारात्मक मापदंडों के कारण, आयातों ने पूंजी निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित नहीं किया है।
- फ. जैसा कि थाईलैंड - एच-बीम्स में निर्णय किया गया था, प्राधिकारी को क्षति का निष्कर्ष निकालने से पहले सभी कारकों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। कई कारकों के सकारात्मक संचलन के मामले में, घरेलू उद्योग को कैसे नुकसान हुआ है, इस बारे में एक अनिवार्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।

- व. नियोजित पूंजी पर 22% की आय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 22% की दर 1976-77 के कीमत नियंत्रण आदेश के आधार पर मानी गई थी, जो एक अलग उद्देश्य के लिए थी। संदर्भ के बिना इसे वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जाना चाहिए; उस अवधि के बाद से व्याज दरों में गिरावट आई है। 20 वर्ष के जीवनकाल पर वास्तविक मूल्यहास और वास्तव में चुकाए गए व्याज पर विचार किया जाना चाहिए।
- भ. ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग और अन्य बनाव निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, यह माना गया था कि 22% की उच्च आय पर विचार करने से एक बड़ी हुई क्षतिरहित कीमत ज्ञात होगी। यूरोपियन फर्टिलाइजर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम काउंसिल के मामले में, यह माना गया था कि लक्ष्य कीमत लाभ मार्जिन तक सीमित होना चाहिए, जिसे कंपनी पाटित आयातों के अभाव में सामान्य परिस्थितियों में यथोचित रूप से प्राप्त कर सकती है।
- म. आवेदक ने याचिका में संभावित गिरावट का प्रदर्शन नहीं किया है, जैसा कि अनुच्छेद 3.4 के तहत जांच के लिए अपेक्षित है।
- य. आवेदक को क्षति, क्षमता विस्तार के लिए किए गए भारी निवेश के कारण हुई है। आवेदक ने अपने द्वारा वहन की गई बड़ी पूंजी लागत को उत्पादन लागत से अलग नहीं किया है। यदि घरेलू उद्योग ने इतनी बार क्षमता में वृद्धि नहीं की होती, तो यह इष्टतम स्तर पर संचालित होता।
- कक. प्राधिकारी के समक्ष दायर 80 प्रतिशत याचिकाएं ऐसी हैं जहां घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है और क्षति क्षमता विस्तार के कारण हुई है।
- खख. आईटीसी ने जांच की अवधि से ठीक पहले क्षमता विस्तार में भारी निवेश किया और 2025 तक और अधिक निवेश करने की योजना है। यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी उद्योग को क्षति हुई है जो इतनी बड़ी मात्रा में निवेश करने में सक्षम है।
- गग. किसी भी आर्थिक मानदंड में गिरावट क्षमता में वृद्धि के कारण है न कि संबद्ध आयातों के कारण क्योंकि शटडाउन के बाद प्रति यूनिट कुल पीवीआईटी और पीवीआईटी में सुधार हुआ है। पूंजी और स्थिर लागत में वृद्धि के कारण यह 2018-19 में और जांच की अवधि में कम रहा। कम लाभप्रदता और 2017-18 के बाद से विक्री की लागत में वृद्धि संयंत्र के बंद होने और क्षमता विस्तार के कारण हुई है जिसके कारण उच्च मूल्यहास लागत हुई। नकद लाभ, जिसमें मूल्यहास शामिल नहीं है, में सुधार हुआ है।
- घघ. कागज की गुणवत्ता, शेड आदि के कारण आवेदक अधिक कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।
- ड.ड. 2019 और 2020 के लिए आईटीसी की वार्षिक रिपोर्ट सकारात्मक मापदंडों और संभावनाओं को दर्शाती है और पाटन के कारण किसी क्षति का उल्लेख नहीं करती है।
- चच. एक सार्वजनिक वक्तव्य में, आईटीसी ने उल्लेख किया कि वह डेकोर पेपर में और निवेश करेगी और पाटन के कारण किसी समस्या का आरोप नहीं लगाया, बल्कि कोविड महामारी को दोषी ठहराया।
- छछ. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत को समस्त नियोजित पूंजी पर 26% आय मानकर बढ़ाया जाता है, जो कि अनावश्यक रूप से अधिक है।
- जज. जांच की अवधि के दौरान ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि., शेडोंग बाँक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं., लि. और किफेंग न्यू मैटेरियल लि. द्वारा निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है और यह चीन जन गण से कुल मात्रा के लिए महत्वहीन है। ऐसे निर्यातों की औसत कीमत और पहुंच मूल्य चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात की तुलना में अधिक है। उक्त निर्यातकों की औसत कीमतों के आधार पर कोई पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नहीं होगा। संबद्ध आयातों का मूल्यांकन घरेलू उद्योग की मांग और उपलब्ध क्षमता में वृद्धि के आधार पर किया जाना चाहिए। संयंत्र के बंद होने और क्षमता विस्तार के बाद भी मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

ज.2. घरेलू उद्योग के विचार

51. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. आवेदक का संयंत्र 2017-18 में कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि आवेदक अपने संयंत्र और मशीनरी का उन्नयन कर रहा था और इस तरह के शटडाउन के प्रभाव को समायोजित किया गया है। तथापि, 2017-18 के मापदंड अन्य वर्षों के साथ तुलनीय नहीं हो सकते हैं।
- ख. संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्षिक रूप से वृद्धि हुई है और भारत में अधिकांश आयातों पर इसका नियंत्रण है।

- ग. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, आयात केवल मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण नहीं बढ़े हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान मांग-आपूर्ति अंतराल से अधिक आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि मांग-आपूर्ति के अंतर में वृद्धि से अधिक है।
- घ. कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ङ. यद्यपि औसत आधार पर कीमत में कटौती नकारात्मक है, यह तीन उत्पाद प्रकारों के लिए सकारात्मक है, जो संबद्ध देश से आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है।
- च. विचाराधीन उत्पादों के लिए कीमत में कटौती का निर्धारण तीन प्रकार के उत्पादों के लिए किया गया था जो उस स्तर पर पीसीएन की अनुपलब्धता के कारण याचिका दायर करने के समय आयात और घरेलू उद्योग की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं।
- छ. इस तर्क के संबंध में कि द्वितीयक आकड़ों पर विचार करने के कारण का खुलासा नहीं किया गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि इसका उपयोग इसलिए किया गया था क्योंकि डीजीसीआईएंडएस आकड़ों में उत्पाद विवरण उत्पाद प्रकार की पहचान को संभव नहीं बनाता है।
- ज. पीसीएन-वार कटौती का निर्धारण हितवद्ध पक्षों द्वारा दायर किए गए उत्तरों के अनुसार किया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को अधिकांश निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं और पीसीएन को डीजीसीआईएंडएस आकड़ों से सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पीसीएन-वार कटौती सकारात्मक है।
- झ. हितवद्ध पक्षों का यह तर्क कि शून्य निर्धारण की अनुमति नहीं है, कानूनी स्थिति के विपरीत है। यूरोपीय समुदाय - ब्राजील से मैलेबल कास्ट आयरन ट्यूबों और पाइपों पर पाटनरोधी शुल्क मामले में पैनल ने माना कि कटौती का निर्धारण सौदा-वार आधार पर और केवल ऐसे आयातों के आधार पर किया जा सकता है जो घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे। प्राधिकारी कीमत कटौती के निर्धारण के लिए नमूने ले सकते हैं।
- ञ. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है क्योंकि इस अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत पर आयात कीमत के मार्क-अप में गिरावट आई है। कच्चे माल की लागत बिक्री मूल्य में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई है।
- ट. संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा।
- ठ. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, तथापि बिक्री में वृद्धि क्षमता के अनुरूप नहीं हुई है।
- ड. कम लाभ पर बिक्री करने के बाद भी घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- ढ. घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ण. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन या बिक्री के अनेक दिवसों के रूप में मालसूची में वृद्धि हुई है।
- त. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। आवेदक ने जांच की अवधि में निवेश पर नगण्य आय अर्जित की है।
- थ. नकद लाभ में वृद्धि के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि बिक्री में वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है। तथापि, यह बिक्री की मात्रा में वृद्धि की तुलना में बहुत कम बढ़ा है। जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में नकद लाभ में गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान प्रति यूनिट नकद लाभ में गिरावट आई है।
- द. घरेलू उद्योग के लाभ में मूल्यह्रास लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक गिरावट आई है।
- ध. हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति को क्षमता विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह 2017-18 में किया गया था और 2018-19 और 2019-20 में पूरी तरह से चालू था। घरेलू उद्योग का प्रदर्शन 2018-19 की तुलना में 2019-20 में खराब रहा।
- न. इस तर्क पर कि पूंजी विस्तार, क्षति के अभाव को दर्शाता है, यह अनुरोध किया जाता है कि क्षमता विस्तार 2017-18 में किया गया था जब घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही थी और क्षमताएं 2018-19 तक पूरी तरह से चालू थीं।
- प. आईटीसी के वक्तव्य के संदर्भ में कि यह अधिक निवेश करेगा और वह कोविड-19 के कारण पीड़ित है, यह अनुरोध किया जाता है कि बयान के संदर्भ से पता चलता है कि यदि आयात में गिरावट आती है तो आवेदक अधिक निवेश करेगा। क्षति की

जांच सार्वजनिक क्षेत्र में दिए गए बयानों के संबंध में नहीं बल्कि प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार की जाती है। कोविड-19 का संदर्भ अप्रासंगिक है क्योंकि जांच की अवधि वर्तमान जांच में कोविड-पूर्व अवधि है।

- फ. मूल्यहास में वृद्धि और नियोजित पूंजी के बीच तुलना क्षमता के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि पहले वाली को रुपये में व्यक्त किया जाता है जबकि बाद वाली को भार के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- ब. घरेलू उद्योग को ईवीआईडीटीए (ब्याज, मूल्यहास, करों और परिशोधन से पहले की कमाई) के संदर्भ में क्षति हुई है, जो बड़ी हुई मूल्यहास लागत के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देती है।
- भ. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, घरेलू उद्योग की लागत पूंजीगत व्यय के कारण नहीं बढ़ी है। इस प्रकार लागत को उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा जाता है बल्कि पूंजीकृत किया जाता है। घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के कारण हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के ईवीआईडीटीए में गिरावट आई है।
- म. घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर 22% की आय पर विचार किया है न कि 26% की आय पर। हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, ट्रिब्यूनल ने कई फैसलों में लगातार यह मत प्रकट किया है कि जब तक हितवद्ध पक्षकार एक अलग आय पर विचार करने की आवश्यकता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, तब तक 22% की आय की अनुमति दी जाएगी। ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का संदर्भ उपयुक्त नहीं है क्योंकि उस मामले में हितवद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य लाए थे कि उत्पाद के लिए वैश्विक प्रतिफल 22% से कम था।
- य. क्षति किसी ज्ञात कारक के कारण नहीं बल्कि संबद्ध आयातों के कारण हुई है।
- कक. इस तर्क पर कि भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा आयातों की मात्रा में गिरावट आई है और कोई पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नहीं होगा, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से आयातों का सत्यापन करना चाहिए क्योंकि विवरणों और पीसीएन में हेराफेरी की प्रबल संभावना है। क्षति का विश्लेषण समग्र रूप से संबद्ध देश के लिए किया जाता है न कि अलग-अलग निर्यातकों के लिए।
- खख. संभावित गिरावट की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदक ने पहले ही कार्यनिष्पादन में वास्तविक गिरावट दर्शाई है और दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं की जाती है।
- गग. हितवद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आवेदक उन्हें गुणवत्तापूर्ण डेकोर पेपर की आपूर्ति करने में असमर्थ है, निराधार है। यदि ऐसा होता तो आवेदक संबद्ध वस्तु की बिक्री नहीं कर पाता। तथापि, इसने क्षति अवधि के दौरान उच्च क्षमता उपयोग स्तरों पर प्रचालन किया है। लैमिनेटर और प्रिंटर दोनों के मामले में इसकी बिक्री में वृद्धि हुई है। सीपीपीआरआई (सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट) की रिपोर्ट और आवेदक की इन-हाउस प्रयोगशाला रिपोर्ट से पता चलता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता चीन जन. गण. से आयातित वस्तु से तुलनीय है। इसके अलावा, इसने मशीनरी में निवेश किया है जो इसे इस श्रेणी के उत्पाद की गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करने में सक्षम बनाता है और वही उत्पाद प्रिंटर और लैमिनेटर द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। आवेदक ने मुख्य ग्रेड के डेकोर पेपर की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की है और कुछ ग्रेडों में बाजार का नेतृत्व किया है।
- घघ. हितवद्ध पक्षकारों को आवेदक की बिक्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि उन्हें किसी गुणवत्ता संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- ड.ड. यह तर्क कि आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट सकारात्मक मानदंड दर्शाती है, गलत है क्योंकि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है और विचाराधीन उत्पाद की बिक्री उसके व्यवसाय का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पृथक सूचना प्रस्तुत की है जो क्षति को दर्शाती है।

ज. प्राधिकारी द्वारा जाँच

ज.3.1 आवेदक के संयंत्र का शटडाउन

52. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के दौरान आवेदक का संयंत्र सात माह से बंद था। आवेदक ने अनुरोध किया है कि संयंत्र का शटडाउन असामान्य प्रकृति का था क्योंकि ऐसा संयंत्र और मशीनरी के उन्नयन के लिए किया गया था। इस तरह के संयंत्र बंद होने के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करने के लिए, प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत समायोजित सूचना पर विचार किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संबद्ध आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक और समायोजित दोनों आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

एच.3.2. मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

53. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	112	188	209
अन्य उत्पादक	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	92	108	91
संबद्ध आयात	एमटी	10,355	27,645	23,817	28,618	36,552
अन्य आयात	एमटी	3,473	4,188	3,608	3,898	3,741
मांग	एमटी	28,832	42,880	42,880	55,520	63,905
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	149	193	222

54. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

55. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिया गया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	10,355	27,645	23,817	28,618	36,552
अन्य आयात	एमटी	3,473	4,188	3,608	3,898	3,741
कुल	एमटी	13,828	31,833	27,425	32,517	40,293
निम्न के संबंध में आयात						
घरेलू उत्पादन	%	70	276	165	121	149
खपत	%	36	64	56	52	57
कुल आयात	%	75	87	87	88	91

56. यह देखा गया है कि :

क. पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

ख. 2017-18 में संबद्ध आयातों में सापेक्षिक रूप से वृद्धि हुई, जब घरेलू उद्योग के संयंत्र को बंदी का सामना करना पड़ा।

ग. कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

छ.3.4 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

57. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करना है या कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती।

क) कीमत कटौती

58. आयातों की पहुंच कीमत की भारत में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत से तुलना करके कीमत कटौती का आकलन किया गया है। इस संबंध में, उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को मिलाकर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर किया गया था। उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार कीमत कटौती की गणना की है जो निम्नानुसार है। यह देखा गया है कि जब आयातों की पीसीएन-वार पहुंच कीमत और निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना की जाती है, तो कुछ पीसीएन में कीमत कटौती सकारात्मक है। चूंकि प्राधिकारी को निर्यातक के उत्तर का 80 प्रतिशत प्राप्त हुआ था, इसलिए पीसीएन वार पहुंच कीमत भागीदार निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तरों से ली गई है।

पीओआई

क्र.सं.	पीसीएन सं.	निवल बिक्री प्राप्ति (रुपये/किग्रा.)	पहुंच कीमत (रुपये/किग्रा.)	कीमत कटौती (रुपये/किग्रा.)	कीमत कटौती (%)	कीमत कटौती (रेंज)
1)	1सी2	***	***	***	***	0-10
2)	2 सी 1	***	***	***	***	20-30
3)	2 सी 2	***	***	***	***	0-10
4)	2यू1	***	***	***	***	0-10
5)	2यू2	***	***	(***)	(***)	(0-10)
6)	3सी1	***	***	(***)	(***)	(0-10)
7)	3सी2	***	***	***	***	0-10
8)	3यू1	***	***	(***)	(***)	(0-10)
9)	3यू2	***	***	***	***	0-10

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

59. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की निम्नानुसार तुलना की गई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
बिक्री लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	116	115

कच्ची सामग्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	137	120	113
विक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	102	109	105
पहुंच कीमत	रू./एमटी	1,28,861	1,36,073	1,36,073	1,39,077	1,28,817
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	106	108	100

60. यह देखा गया है कि 2017-18 में विक्री की लागत और कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। तथापि, विक्री कीमत और पहुंच मूल्य दोनों में 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है और विक्री की लागत में आधार वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। तुलनात्मक रूप से, संबद्ध वस्तु की विक्री कीमत में केवल 5% की वृद्धि हुई है, जबकि पहुंच मूल्य में कमी आई है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।

ज.3.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

61. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों का एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतक, जिसमें विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, नियोजित पूंजी पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और विक्री की मात्रा

62. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, विक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार था:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	109	226	226
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	101	199	219
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	93	88	97
घरेलू विक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	112	188	209
निर्यात विक्रिया	एमटी	-	-	-	-	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	100

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्पादन और घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 2018-19 तक गिरावट आई लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। फिर भी, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षति अवधि की शुरुआत की तुलना में कम रहा।

ख) बाजार हिस्सा

64. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाये गये अनुसार रहा था।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	180	155	144	159
अन्य आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	70	58	49
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	75	98	94
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	62	56	41
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%

65. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली कमी आई है। समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में काफी कमी आई है, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ग) मालसूची

66. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	87	33	104
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	38	38	120	194
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	64	73	146

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जो मालसूची के संचय को दर्शाता है। मालसूची के औसत स्तर ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 46% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
बिक्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	116	115
बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	102	109	105
लाभ/(हानि)	रू./एमटी	***	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(59)	37	39	10
लाभ/(हानि)	लाख रुपये	***	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	Indexed	100	(35)	41	74	21
नकद लाभ	रू./एमटी	***	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(42)	39	83	53
नकद लाभ	लाख रुपये	***	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(25)	44	156	111
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(11)	13	19	6

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को 2017-18 में घाटा हुआ, जब उसका संयंत्र बंद हो गया था। तथापि, 2018-19 के दौरान इसकी लाभप्रदता में सुधार हुआ लेकिन जांच की अवधि के दौरान फिर से गिरावट आई है। इसके अलावा, यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कुल नकद लाभ में वृद्धि हुई है, प्रति यूनिट नकद लाभ में कमी आई है। नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है और घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नगण्य आय अर्जित किया है।

ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

70. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	55	126	127
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	188	160	175
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	100	200	222
मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	77	99	107
प्रति यूनिट मजदूरी	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	76	50	49

71. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है, तथापि प्रति यूनिट मजदूरी में गिरावट आई है।

च) पाटन की मात्रा

72. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं को भारत में पाटित किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

छ) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
क्षमता	%	-	(48)	9	335	-
उत्पादन	%	-	(52)	1	311	10
घरेलू विक्रियां	%	-	(40)	12	216	11
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	%	-	(159)	(63)	167	(74)
नकद लाभ	%	-	(125)	(56)	728	(29)
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	(111)	(87)	277	(69)

73. यह नोट किया जाता है कि क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री ने क्षति अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग के सभी लाभप्रदता मानकों ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। लाभप्रदता मापदंडों ने 2018-19 में वृद्धि दर्शाई, लेकिन उसके बाद जांच की अवधि उसमें फिर से गिरावट आई।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ और आय में जांच की अवधि में गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि पाटित आयातों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित किया है।

झ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है और वे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। परिणामस्वरूप, यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत

में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, ऐसी वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि से कम है। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

व) क्षति मार्जिन

76. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय प्रभावित नहीं किया जाए। नियमावली के अनुबंध III में यथा विहित विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व 22% की दर से) को क्षति रहित कीमत ज्ञात करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में निर्धारित किया गया था और उसका पालन किया जा रहा है।
77. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबद्ध देश के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।
78. पहुंच कीमत और ऊपर यथा निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और इसे नीचे तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	पीसीएन	एनआईपी (रु./एमटी)	पहुंच मूल्य (रु./एमटी)	क्षति मार्जिन (रु./एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडा./एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रैंज)
		चीन जन. गण.						
1)	किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लि.	1सी2	***	***	***	***	***	30-40
		2सी1	***	***	***	***	***	0-10
		2सी2	***	***	***	***	***	30-40
		2यू1	***	***	***	***	***	20-30
		2यू2	***	***	***	***	***	10-20
		3सी1	***	***	***	***	***	20-30
		3सी2	***	***	***	***	***	20-30
		3यू1	***	***	***	***	***	10-20
		3यू2	***	***	***	***	***	10-20
	कुल भारत औसत		***	***	***	***	***	10-20
2)	शानडोंग बोक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कंपनी लि.	3सी1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0)-(10)
3)	जिबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कंपनी लि.	2सी1	***	***	***	***	***	10-20
		2यू1	***	***	***	***	***	30-40
		3सी1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0)-(10)

		3यू1	***	***	***	***	***	20-30
	कुल भारत औसत (शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड और जिबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड)		***	***	***	***	***	10-20
4)	असहयोगी/अवशिष्ट निर्यातक		***	***	***	***	***	50-60

ज.3.6 क्षति का समग्र आकलन

79. विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच से पता चलता है कि:

- आयात की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत दोनों दोनों की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- आयातों ने कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा बढ़ गई होती।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्री और क्षमता में वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग की मालसूची के औसत स्तर में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग के प्रति यूनिट लाभ और नकद लाभ में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर केवल नाममात्र की आय अर्जित कर रहा है।
- यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है, तथापि लाभप्रदता मापदंडों ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।
- आयातों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए पूंजी निवेश को जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित किया है।
- पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

80. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज.3.7. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

81. क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए पाटित आयातों के अलावा, नियमावली के अधीन यथा सूचीबद्ध किसी अन्य कारक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

82. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के आयातों के अलावा, संबद्ध वस्तुओं के अधिकांश आयात यूरोपीय संघ से हुए हैं। तथापि, ऐसे आयातों की कीमत संबद्ध आयातों की कीमत से कहीं अधिक है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ से आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से अधिक रही है। संबद्ध देश और यूरोपीय संघ के अलावा, अन्य देशों से आयात मात्रा में नगण्य हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ख) मांग में संकुचन

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ी है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत की प्रवृत्ति

84. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की खपत की प्रवृत्ति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच से यह पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह नहीं पता चला है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च) उत्पादकता

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसलिए घरेलू उद्योग को इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यानिष्पादन

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में अपने उत्पादन के एक छोटे हिस्से का निर्यात किया है। तथापि, यथोक्त जांच की गई क्षति सूचना का संबंध केवल घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार में कार्य निष्पादन के संदर्भ में है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ज) अन्य उत्पादों का कार्यानिष्पादन

89. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के कार्यानिष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्यानिष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज.3.8. कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

90. यद्यपि नियमावली के अधीन सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

क. भारत में संबद्ध वस्तुओं का भारी पाटन हो रहा है।

ख. पाटित आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और खपत के संबंध में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

ग. परिणामस्वरूप, संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी आई है।

घ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ङ. आयातों ने घरेलू उद्योग को उसकी बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि करने से रोककर उसकी कीमतों में ह्रास किया है।

च. प्रति यूनिट लाभ और नकद लाभ में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

छ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर केवल मामूली आय अर्जित कर रहा है।

91. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि क्षमता विस्तार के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 2017-18 में क्षमता विस्तार पूरा कर लिया है, जिसके बाद 2018-19 में इसके कार्यानिष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग के कार्यानिष्पादन में जांच की अवधि के दौरान फिर से गिरावट आई है, जिसके लिए क्षमता विस्तार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का ईवीआईडीटीए (व्याज, मूल्यह्रास,

कर और परिशोधन से पहले की आय), जो कि बड़े हुए मूल्यहास या वित्त लागत से प्रभावित नहीं है, वर्तमान अवधि में भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इसलिए, इस क्षति के लिए क्षमता विस्तार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2017-18 समा.	2018-19	पीओआई
ईवीआईडीटीए (व्याज, मूल्यहास, कर और परिशोधन पूर्व आय)	रु./एमटी	***	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(42)	39	83	53

92. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. प्रकटन पश्चात की टिप्पणियाँ

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में आयात किया गया है। नियम 2(ख) के तहत केवल जांच की अवधि के दौरान किए गए आयातों की जांच को सीमित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
- ख. चूंकि कीमत कटौती नकारात्मक है, अतः घरेलू उद्योग की क्षति को पाटित आयातों के कारण से नहीं कहा जा सकता।
- ग. याचिकाकर्ता की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नकारात्मक नहीं है। घरेलू उद्योग की कम लाभप्रदता, रंगों के लिए छोटे बैचों के लिए आदेश लेने में इसकी अक्षमता के कारण से है क्योंकि इसके लिए चीन जन. गण. के लिए 5 टन अथवा यूरोपीय संघ के लिए 1 टन की तुलना में 30 टन की न्यूनतम मात्रा के आदेश आवश्यक होता है।
- घ. प्रकटीकरण विवरण में यह प्रकट नहीं किया गया है कि पूंजी लागत/ क्षमता वर्धन के लिए वित्त लागत के प्रभाव को कैसे उत्पादन की ईष्टतम लागत के निर्धारण के लिए माना गया है, जिसे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया गया है।
- ङ. ओहुआ के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का सही निर्धारण नहीं किया गया है। चूंकि ओउमू और कुईफेंग, ओहुआ की विस्तारित शाखाएं हैं, अतः ओहुआ द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ और प्रत्यक्ष एसजीए के लिए कोई भी कटौती किए जाने की जरूरत नहीं है।
- च. पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण छोटे पैमाने के प्रयोक्ताओं के हित के लिए किया जाएगा, जो 5 मी. टन अथवा कम के बैचों में आदेश देते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग के पास समग्र मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता है, और वह 30 मी. टन से कम के आदेश लेने के लिए इच्छुक नहीं है।
- छ. पीसीएन-वार कीमत कटौती पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि सभी आयात संबंधी सौदे शामिल न हों। केवल इस कारण से कि प्रतिवादी पक्षकारों के पास भारत में कुल आयातों का 80 प्रतिशत हिस्सा है, यह नहीं माना जा सकता कि वे शेष 20 प्रतिशत आयातों के लिए पीसीएन-वार आयात प्रवृत्ति के प्रतिनिधि हैं।
- ज. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनका लाभ मार्जिन काफी कम है। विचाराधीन उत्पाद तैयार माल के उत्पादन की कुल लागत का लगभग 6% है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। डेको मीका के लिए लाभ मार्जिन केवल 1.4% है, जबकि एआईसीए के लिए यह केवल 8% है।
- झ. अपाटित आयातों पर मात्रा और कीमत संबंधी विश्लेषण के प्रयोजन से विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- ञ. उत्पाद स्तर और देश स्तर पर भारित औसत मूल्य कटौती का खुलासा नहीं किया गया है।

- ट. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए गए उत्पाद प्रकारों/पीसीएन के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का खुलासा किया जाना चाहिए।
- ठ. पीसीएन 2 यूआई के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत ही अधिक है। घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है न कि यह उत्पादन की वास्तविक लागत को दर्शाता है।

झ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

94. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
- क. श्री कृष्ण पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी संबद्ध आयातों के पाटन के कारण क्षति का सामना कर रही है क्योंकि उसके उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में, क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ख. लोक हित के संबंध में पाटनरोधी उपायों के प्रभाव पर घरेलू उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योग तथा आम जनता सहित विभिन्न प्रकार के पक्षकारों के हितों की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग में तीन उत्पादक शामिल हैं। यदि पाटन को नहीं रोका गया और क्षति जारी रहती है, तो याचिकाकर्ता को अपने प्रचालनों को बंद करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को आयातों पर निर्भर होना पड़ेगा।
- घ. लेमिनेट उद्योग ने कई गुणा वृद्धि की है, जिसमें इसका निर्यात वर्ष 2012 में 500 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2020 में 2000 करोड़ रु. हो गया है। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है और इस प्रकार आयातित विचाराधीन उत्पाद उचित कीमत पर उपलब्ध हैं, अतः लेमिनेट उद्योग घरेलू उत्पादकों से विचाराधीन उत्पाद की खरीद करना पसन्द करेगा।
- ड. घरेलू उद्योग अन्य गुणवत्ता के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है और उपभोक्ता स्वदेशी माल से उत्पादित उत्पाद पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं।
- च. यद्यपि याचिकाकर्ता का भारतीय बाजार में एक दीर्घावधिक हित है, क्योंकि यह सन् 1910 से भारत में एक जाना पहचाना नाम है और यह विभिन्न बाजारों में शामिल है, लेकिन निर्यातक का हित लाभों को अधिकतम करने तक सीमित है। यदि उनके पास बेहतर कीमतें उपलब्ध हैं, तो निर्यातक बाजार से बाहर जाने के लिए नहीं हिचकिचाएगा।
- छ. चूंकि आयातों के मामले में आदेश देने और डिलीवरी प्राप्त करने के बीच का समय काफी अधिक होता है, अतः प्रयोक्ताओं के संबद्ध वस्तुओं की बड़ी वस्तुसूचियां रखनी होगी। इससे प्रयोक्ताओं की लागतों में वृद्धि होगी।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

95. प्राधिकारी ने अन्य हितवद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट किया है कि यद्यपि अधिकांश टिप्पणियां पुनः की गई हैं, जिनकी पहले ही समुचित रूप से जांच की जा चुकी है और जांच परिणामों के संगत पैरा में उपयुक्त रूप से विचार किया जा चुका है, अतः प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए नए मामलों की जांच की है।
- क. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के दायरे से याचिकाकर्ता को बाहर करना चाहिए क्योंकि उसने विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है, अतः यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017-18 में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, जो उस वर्ष में कुल आयातों का केवल 7 प्रतिशत तक है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान कोई भी आयात नहीं किए गए हैं। साथ ही, नियम 2 (ख) के तहत विशेष रूप से ऐसे उत्पादकों की पात्रता का उल्लेख किया गया है, जो "कथित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध हैं अथवा वे स्वयं ही उसमें आयातक हैं" साथ ही, आवेदक भी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ने यह पाया है कि उत्पादक, घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।
- ख. कुछ पीसीएन के लिए नकारात्मक कीमत कटौती के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत कटौती अन्य क्षति मापदंडों में से एक मापदंड है, जैसा कि यहां उन पर निष्कर्ष भी दिया गया है। संबद्ध आयातों का कीमतों पर अधिक भार पड़ा है और उसका घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण का प्रभाव था। घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर संबद्ध आयातों के पाटन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- ग. जहां तक नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नकारात्मक न होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि अनुबंध-II के तहत प्राधिकारी से यह निर्धारण करने की अपेक्षा है कि क्या नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में एक स्वाभाविक और संभावित गिरावट आई है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में कोई गिरावट है, तो प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घरेलू उद्योग को, यदि सकारात्मक प्रतिफल है, तब भी उस मापदंड के संदर्भ में क्षति हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत/ क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत लागत/ वित्त लागत व्यवस्था के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूंजीगत व्यय के लिए लागत उत्पादन की लागत में शामिल नहीं की गई है, लेकिन भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार पूंजीकृत की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने किसी वित्त लागत का दावा नहीं किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत का उपयुक्त रूप से निर्धारण किया गया है और यह बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाई गई है।
- ड. ओहुआ के लिए निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि वह भारत को संगत संस्थाओं, ओउमु और कुइफेंग के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, अतः संगत संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए लाभ और किए गए प्रत्यक्ष एसजीए व्यय को समायोजित किए जाने की जरूरत है, ताकि प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार ओहुआ के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।
- च. प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में, चूंकि लाभ मार्जिन कम है, अतः प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लाभों की, वित्तीय विवरणों के अनुसार जांच की है। प्रयोक्ताओं के लाभ आयातों की पहुंच कीमत के साथ कोई सहसंबंध नहीं दर्शाते। प्रयोक्ताओं ने, यहां तक कि आयातों की पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है, कम मार्जिन का दावा किया है। प्रयोक्ताओं ने यह नहीं दर्शाया है कि उन्हें हानियों का सामना करना पड़ा है, जबकि आयातों की कीमत अधिक थी। इसके प्रतिकूल, प्रयोक्ताओं के वित्तीय विवरणों का सारांश, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया है, यह दर्शाता है कि प्रयोक्ताओं का लाभ मार्जिन इन अवधियों के दौरान अधिक था, जबकि आयात कीमत अधिक थी। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को हानि उठानी पड़ रही है।

व. भारतीय उद्योग हित और अन्य मुद्दे

व. 1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध

96. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. डेकोर पेपर प्रिंटिंग उद्योग भारत में खुद को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह सीमित आपूर्ति विकल्पों और प्रिंट बेस पेपर की आवश्यक गुणवत्ता की अनुपलब्धता के कारण विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए बाध्य है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए प्रिंट बेस पेपर की गुणवत्ता सुचारु होने और रंग अवशोषण क्षमता के मामले में प्रयोक्ता उद्योग के गुणवत्ता मानकों से मेल नहीं खाती है जिसके कारण अस्वीकृति दर उच्च होती है। इसलिए, प्रयोक्ताओं को उत्पाद आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- ग. गुणवत्ता के मामले में आयातित वस्तुओं और घरेलू सामानों के बीच बिल्कुल एकसमान तुलना नहीं हो सकती है। गुणवत्ता के कारण डेकोर पेपर को अस्वीकृत करने से प्रिंटर को कोई लाभ नहीं मिलता है।
- घ. प्रिंटर को प्री-प्रिंटेड डेकोर पेपर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें प्रिंट बेस पेपर, प्रिंटिंग इंक, इंक वाइंडर, मशीनरी, उपकरण, प्रिंटिंग सिलेंडर आदि का आयात करने की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है।
- ड. केवल विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क लगाने से संबद्ध देश से मुद्रित डेकोर पेपर सस्ता हो जाएगा, जिससे प्रिंटरो को कड़ी कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप ऐसे उत्पाद का पाटन हो सकता है जिससे भारतीय मुद्रण उद्योग विलुप्त हो जाएगा, जिससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- च. विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देश के डेकोर प्रिंटरो को घरेलू प्रिंटरो पर अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। यदि प्री-प्रिंटेड डेकोर पेपर के आयात में तेजी आती है, तो कई घरेलू प्रिंटरो को बंद करना पड़ सकता है जो मेक इन इंडिया पहल के विपरीत होगा।

- छ. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि डेकोर पेपर का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, आवेदक देश में मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है और मांग-आपूर्ति में भारी अंतर है। इसलिए, आयात अपरिहार्य हैं और उपयोगकर्ताओं को ऐसे आयातों पर शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। संबद्ध वस्तुओं की खपत बड़ी संख्या में डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं, अधिकांशतः एमएसएमई क्षेत्र में की जाती है।
- ज. क्षमताओं के विस्तार और 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन के बाद भी घरेलू उद्योग घरेलू मांग का केवल 50 प्रतिशत ही पूरा कर सकता है। ऐसे मामले में, पाटनरोधी कानून लागू करने का एकमात्र उद्देश्य पूंजीगत लागत की वसूली के लिए असाधारण लाभ प्राप्त करना है।

ज.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

97. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. यदि आवेदक को क्षति लंबे समय तक बनी रहती है, तो आवेदक को अपना संचालन बंद करना पड़ सकता है। चूंकि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है, ऐसे में उपभोक्ताओं को आयात पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा।
- ख. प्रयोक्ताओं ने अपने कार्यनिष्पादन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के किसी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं किया है।
- ग. पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपयोक्ता के हित पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमतों पर प्रभाव नगण्य होगा और वह इस तरह की वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डालने में सक्षम होगा।
- घ. प्रयोक्ताओं का कार्यनिष्पादन आयातों की कीमत पर निर्भर नहीं है क्योंकि उनका निष्पादन 2016-17 में सबसे अच्छा था जब कच्चे माल की कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का मार्कअप उच्चतम था और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी। जब आयात की कीमतें अधिक थीं तब उपयोगकर्ता अप्रभावित थे। पहुंच मूल्य में गिरावट के साथ उपयोगकर्ताओं के कार्यनिष्पादन में गिरावट देखी गई है।
- ङ. यह नहीं माना जा सकता है कि उचित कीमत पर वस्तु की उपलब्धता के कारण उपयोगकर्ताओं का संचालन अव्यावहारिक हो जाएगा। उपयोगकर्ता पाटित कीमतों पर माल की उपलब्धता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
- च. आत्म निर्भर भारत की दिशा में बढ़ने के लिए आवेदक ने क्षमता विस्तार के लिए भारी राशि का निवेश किया है। देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए इस तरह के निवेश का संरक्षण करने और आगे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
- छ. निवेश और निवेश की लागत की वसूली के लिए आवेदक के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करना आवश्यक है क्योंकि डेकोर पेपर उद्योग की प्रकृति पूंजी प्रधान है। वर्तमान में, आवेदक का लाभ वित्तपोषण की लागत के 10% से अधिक को कवर करने के लिए अपर्याप्त है।
- ज. पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पाद में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।
- झ. इस तर्क के संबंध में कि देश में मांग-आपूर्ति का अंतर है और पाटनरोधी शुल्क का एकमात्र उद्देश्य असाधारण लाभ प्राप्त करना है, यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध वस्तु की उपलब्धता सीमित नहीं होगी बल्कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति ही स्थापित होगी। नोसिल लिमिटेड बनाम भारत सरकार मामले में उच्च न्यायालय ने यह माना था कि मांग-आपूर्ति अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं बनाता है। डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने माना था कि निर्यातक इस बहाने से पाटन नहीं कर सकते हैं कि घरेलू उद्योग भारत में मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। प्राधिकारी ने उन मामलों में भी जहां मांग-आपूर्ति में अंतर था, पाटनरोधी शुल्क लगाने की लगातार सिफारिश की है।
- ञ. चीन जन गण. की सरकार द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदान की गई सहायता ने भारत में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नष्ट कर दिया है। उत्पादक/निर्यातक स्वीकार करते हैं कि उनकी लागत और कीमतें सरकार के हस्तक्षेप से प्रभावित होती हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी पक्ष ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की मांग नहीं की है।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचानी गई चुनौतियों में यह शामिल है कि वे संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आवेदक घरेलू स्तर पर इसे प्रदान कर रहा है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

98. रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की है। प्रयोक्ता उद्योग ने उन मानकों के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिनमें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पादों का मुकाबला नहीं करते। तथापि, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीपीआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आयातित वस्तु के मापदंडों और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई वस्तु के मापदंडों में संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता में मामूली अंतर है।
99. कुछ हितवद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि यदि प्री-प्रिंटेड डेकोर पेपर पर शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो उसका पाटन शुरू हो जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित है जिसमें पूर्व-मुद्रित डेकोर पेपर शामिल नहीं है। यदि पूर्व-मुद्रित डेकोर पेपर का पाटन शुरू हो जाता है, तो घरेलू उत्पादक उक्त उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
100. कुछ हितवद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात अपरिहार्य हैं और उन्हें आयात के लिए उच्च कीमत चुकाने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर भारत में पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। देश में मांग-आपूर्ति का अंतर होने पर भी यह आवश्यक है कि उत्पाद उचित कीमत पर उपलब्ध हो। पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता में बाधा नहीं आएगी बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि यह उचित कीमत पर उपलब्ध है। वास्तव में, बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थापना से और निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है, जो मांग-आपूर्ति के अंतर को और पाटने में मदद करेगा।
101. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उत्पाद को अन्य देशों जैसे इटली, जापान, जर्मनी और पोलैंड से भी आयात किया जा सकता है, साथ ही घरेलू स्तर पर माल की सोर्सिंग भी की जा सकती है। किसी भी मामले में, देश में संबद्ध वस्तुओं के केवल तीन उत्पादक हैं, जिनमें याचिकाकर्ता सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि मौजूदा स्थिति बनी रहती है, तो घरेलू उद्योग के संचालन की व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है। इसलिए, घरेलू उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि घरेलू उत्पादक उचित कीमतों पर व्यवहार्य बने रहें, ऐसा न करने पर उपयोगकर्ता पाटित आयातों पर अधिकाधिक निर्भर हो जाएंगे। कोविड -19 अवधि में हाल के अनुभव से यह भी पता चला है कि यदि उपयोगकर्ता आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं तो उन्हें नुकसान होता है।
102. घरेलू उद्योग के प्रचालनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन के लिए दीर्घावधिक प्रतिबद्धता दिखाई है। देश में महत्वपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण राशि का निवेश किया है। ऐसा होने पर, इसे अपने निवेश की वसूली के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करने की आवश्यकता है। हालांकि, फिलहाल इसका मुनाफा काफी कम है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यदि उसने अपने संयंत्र को ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया होता, तो वर्तमान में अर्जित लाभ 9% की व्याज दर को मानते हुए, वित्त लागत का केवल 10% कवर करेगा। इसलिए, ऐसी बाजार स्थिति देश में और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नहीं होगी।
103. उपयोगकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि शुल्क लगाने से उनके मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद उनकी उत्पादन लागत का 6% है, और वे कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि प्रयोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव 0.66% से 1.64% होगा। यह मानते हुए भी कि विचाराधीन उत्पाद प्रयोक्ताओं की उत्पादन लागत का 6% है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुशंसित शुल्क 10% से कम है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने पाया कि शुल्क से अधिकतम 0.6% की वृद्धि होगी, जिसे महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है।
104. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ दूर हो जाएंगे, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाम करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

105. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
 - आवेदन में जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए सभी संगत सूचना निहित हैं और आवेदन में, जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य निहित हैं।
 - संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
 - घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है। संबद्ध आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा में, घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त क्षमता वृद्धि किए जाने के बावजूद, पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मापदंडों में क्षति अवधि के दौरान एक नकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई है।
 - घरेलू उद्योग को क्षति, संबद्ध देश से पाटन आयातों के कारण हुई है।
 - रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क न लगाने से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल और पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा, जबकि शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग अथवा व्यापक रूप से जनता पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और की गई जांच के आधार पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित के खिलाफ नहीं होगा।
106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितवद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और जांच किए जाने पर प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
107. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं; इस प्रयोजन के लिए पट्टा मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित और सीमा शुल्क के लागू स्तर पर आकलन योग्य मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	48059100, 48022090	डेकोर पेपर*	चीन जन. गण	चीन जन. गण	किंग डेकोर (झेजियांग) कं., लि.	116	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर\$
2.	48059100,	डेकोर	चीन जन.	चीन जन.	शानडोंग वॉक्सिंग	110	मीट्रिक टन	अमेरिकी

	48022090	पेपर*	गण	गण	ओहुआ स्पेशल पेपर कं., लि. एंड जिवो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं., लि.			डॉलर\$
3.	48059100, 48022090	डेकोर पेपर*	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	क्र. सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य	542	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर\$
4.	48059100, 48022090	डेकोर पेपर*	चीन जन. गण. से इतर कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई	542	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर\$

*40-130 जीएसएम, रील फार्म में कोट न किया गया पेपर है जिसमें कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट की विलय करने के क्लेम, 10-40 सेकेंड/ 100 एमएम की गरली पोरसिटी और 6-12 एन/ 15 एमएम की वेट टेंसाइल क्षमता है और जिसमें फ़िलर के रूप में टाइटेनियम डाई ऑक्साइड अथवा पिगमेंट यह उच्च दबाव (एचपीएल) अथवा निम्न दबाव (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट्स के लिए बेस पेपर है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च दबाव अथवा निम्न दबाव के लेमिनेट के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर परंतु जिसमें उपयोग करने के लिए तैयार प्रिंटेड डेकोर पेपर शामिल नहीं है, के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर जैसे सर्फेसिंग पेपर (व्हाइट/ ऑफ व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ ऑफ व्हाइट), बेरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (क्लर/ व्हाइट) शामिल हैं। इसका आयात वेक्सिन, कोटिंग और इम्प्रेगेशन के लिए बेस पेपर; प्रिंटिंग के लिए बेस पेपर; डेकोरेटिव उद्योग में उपयोग किए जाने के लिए बेस पेपर और बेरियर पेपर के रूप में आयात किया जा सकता है और ये विभिन्न आकारों जैसे 95 सीएम, 96 सीएम, 102 सीएम, 123 सीएम, 123.5 सीएम, 124 सीएम, 124.5 सीएम, 125 सीएम, 131 सीएम, 132 सीएम, 183 सीएम, 184 सीएम तथा 185 सीएम के रूप में आ सकता है।

ठ. आगे की प्रक्रिया

108. इस सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष की जा सकेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2021

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI) – 33/2020

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Decor Paper” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/38/2020-DGTR- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

- The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received an application from M/s ITC Limited Paperboards and Specialty Papers Division (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “petitioner” or the “domestic industry” or “DI”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as

amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules" or the "AD Rules") for imposition of anti-dumping duty on the imports of "Decor Paper" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods") originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").

3. And whereas, in view of a duly substantiated application filed by the applicant, showing prima facie dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/38/2020-DGTR dated 30th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation into the imports of the product under consideration originating in or exported from the subject country in accordance with the Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with the Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the import of the subject goods from the subject country.
 - c. The Embassy of the subject country in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules. The Authority e-mailed a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available to the other interested parties, wherever requested, through e-mails.
 - e. The Authority sent Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters in the subject country to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Changle Keyuan Paper Company Limited
 - ii. Hangzhou Huawon New Material Technology Company Limited
 - iii. Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.
 - iv. Qifeng New Material Ltd.
 - v. Xianhe Co., Ltd.
 - f. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and the questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy along with the list of the known producers/ exporters from the subject country.
 - g. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing the questionnaire response:
 - i. Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. China PR
 - ii. Qifeng New Material Ltd., China PR
 - iii. Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.
 - iv. Xianhe Co., Ltd.
 - v. Zhejiang Xianhe New Materials Sales Co., Ltd.
 - vi. Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.

- h. The Authority sent the importer's questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with the Rules.
- i. Century Plyboards I Limited
 - ii. Color Experts
 - iii. Fakirson Papchem Private Limited
 - iv. Fancy Roto Prints
 - v. Greenlam Industries Limited
 - vi. JKS Decor Paper LLP
 - vii. Merino Industries Limited
 - viii. Maruti Decor
 - ix. Maruti Paper Chem
 - x. Match Graphics Private Limited
 - xi. Matchwell
 - xii. Mbee Paper Prints Private Limited
 - xiii. Microteck Printage Private Limited
 - xiv. Pixel Printers
 - xv. Printech Industries
 - xvi. Sanwaliya Impex LLP
 - xvii. Saraf Sales Corporation
 - xviii. Saya Paper Print Private Limited
 - xix. Shindecor
 - xx. Shivam Paper Print
 - xxi. Silver Paper Print
 - xxii. Slick Mica Private Limited
 - xxiii. Stylam Industries Limited
 - xxiv. Surface Dekor Private Limited
 - xxv. Tanish Industries Private Limited
 - xxvi. Unique Decor (India) Private Limited
 - xxvii. Vinayak Decor
 - xxviii. Vision Printers
- i. The Authority sent the questionnaire to the following known Associations of the subject goods in India for circulation and calling for the necessary information in accordance with the Rules:
- i. Associated Chambers of Commerce and Industry of India
 - ii. Confederation of Indian Industry
 - iii. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry
 - iv. Indian Laminate Manufacturer's Association
- j. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers/users have responded by filing the questionnaire response:
- i. Aica Laminates India Private Limited
 - ii. Deco Mica Limited
 - iii. Fakirsons Papchem Private Limited
 - iv. JKS Decor Paper LLP

- v. Match Graphics Private Limited
- vi. Saraf Sales Corporation
- k. The Authority sent notice of initiation to the following other domestic producers, intimating them of the initiation of investigation, with a request to provide relevant information to the Authority in the form and manner prescribed:
 - i. Pudumjee Paper Products
 - ii. Shree Krishna Papers
- l. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions on physical movement imposed by different countries, including India, the Authority circulated the non-confidential version of the evidence presented by the domestic industry and the various interested parties to the other interested parties for inspection by the other interested parties.
- m. The request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of the imports and its analysis after due examination of the transactions.
- n. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as the "POI") in the present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020. The injury period will cover the periods 1st April, 2016- 31st March, 2017, 1st April, 2017-31st March, 2018, 1st April 2018-31st March, 2019 and the POI.
- p. Considering the fact that the subject goods are being imported under various types, the applicant proposed the Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN-to-PCN comparison for the injury examination.
- q. The Authority invited the views from the interested parties regarding the PCN methodology proposed by the domestic industry. All the interested parties were requested to make their views known in writing within 7 days of the issuance of the letter.
- r. The Authority finalized the PCNs vide letter dated 3rd May, 2021, pursuant to which the interested parties filed the PCN wise Information.
- s. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions on physical movement imposed by different countries, including India, the physical inspection through on-the-spot verification of the information was not carried out by the Authority. The desk verification of the information provided by the applicant/producers/ exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information, to the extent deemed necessary, has been relied upon for the purpose of this investigation.
- t. The Authority, in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April, 2020, conducted an oral hearing through video conferencing on 16th June, 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present their views orally before the Authority.
- u. All the parties who had attended the above-mentioned oral hearing were advised to file the written submissions by 23rd June, 2021 of the views expressed orally, followed by the rejoinders, if any, by 29th June, 2021. The arguments made in such written submissions and the rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent deemed necessary, for the purpose of this investigation.
- v. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 15.09.2021 and the interested parties were allowed time upto 22.09.2021 to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification
- w. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final finding notification.

- x. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claim wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide the sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- y. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such a party as non-cooperative and recorded its views/observations on the basis of the facts available.
- z. The Authority has considered all the arguments raised and the information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation and have formed the basis for conclusions in the final findings.
- aa. ‘***’ in this final finding notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- bb. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND THE LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration is “uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler” (herein also referred to as “Decor paper” or “subject goods”). It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper.

4. The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white). It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.

5. The product under consideration is produced from pulp, in the form of pressed sheets, which have to be slush in water to make pulp suspension so that pulp is suitable for use. During this process, fibres are separated. To produce decor paper, fibres are refined through the action of mechanical work and in the presence aqueous medium (water). Additives are added in the manufacturing process, which are used as filler in the spaces between fibres, with the aim of improving opacity, whiteness and to increase the quality of print by improving the surface. Thereafter, undesirable particles are removed through cleaning. A volume of diluted pulp suspension is next transformed into a fine, wide and uniform sheet, with all components perfectly distributed, post which the sheet is dewatered, dried and calendared. Lastly, the sheets are slotted as per the requirements, and packed.

6. The product under consideration is classified under the Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff customs classification 48059100. The Applicant has claimed that the product under consideration is also being imported under 48022090. Both the customs classifications have been considered for the purpose of the present investigation. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

C.1 Views of the other interested parties

- 6. The submissions of the other interested parties with regard to the product under consideration and the like article are as follows:
 - a. Printed decor paper is a form of decor paper and cannot be excluded from the scope of the product under consideration as it is a like article to the product under consideration.
 - b. The reason behind exclusion of printed decor paper is not tenable. The absence of the duty on the printed decor paper will be injurious and detrimental to the users as well as the domestic industry, as it may lead to the increase in the imports of printed decor paper from the subject country.

- c. The exclusion of printed decor paper from the scope of the product under consideration will result in circumvention of the anti-dumping duty as the imported printed decor paper will become cheaper than the domestically produced product. Pre-printed decor paper imported from the subject country has the same description as the product under consideration except the printing.
- d. The product under consideration should be limited to 40-90 GSM as the domestic industry produces between this range as cited on its website. In investigations on coated paper and newsprint, the Authority excluded the product under consideration not manufactured by the domestic industry.
- e. The petitioner does not produce the product under consideration over 100 GSM and, therefore, cannot seek for the anti-dumping duty on it. Mere capabilities to produce over 100 GSM is not sufficient evidence. The product over 100 GSM must be excluded from the scope of the product under consideration.
- f. Titanium dioxide used in the manufacturing of the subject goods in India has lower whiteness and low light resistance covering rate as compared to that in China PR. As the content of titanium dioxide is low in India, it should be excluded from the scope.
- g. The Authority should confirm that ready-to-use decor paper is excluded from the scope of product under consideration regardless of any colour, including white ready-to-use decor paper.
- h. The product under consideration is two different types of papers, one used directly by laminators and the other used by the printers which manufacture the printed paper for laminating sector. The papers used directly by the laminators have distinct technical specification and quality parameter and command higher cost and price as compared to the paper used by the printers. Each type and sub-type of decor paper is not technically and commercially substitutable. The paper manufacturers pre-decide whether to make decor paper for the laminators or the printers. The applicant has not explained the difference between the production process of decor paper meant for use by the laminators and the printers.
- i. The applicant is mainly producing print base paper with lower GSM. The laminating industry is largely dependent upon the imports as the production and the sale of the base paper for laminates by the applicant is negligible.
- j. Any type or subtype not produced and supplied by the applicant in substantial quantity should be excluded from the scope of the product under consideration.
- k. The application should not be considered as a parameter for the PCNs as it does not influence the cost and price. The exporters will have difficulty in distinguishing products by application as they do not have the knowledge of the customers usage.
- l. Simply because the product is misclassified or mis-declared cannot be the grounds for inclusion of 4802 20 90 in the scope of the duties. The inclusion of this code would result in practical difficulties for the importers while clearing the goods that actually fall under this code.
- m. The excluded printed decor paper has different HSN code, i.e., 48119099, and is also referred to as 'pre-printed décor paper'. It is also produced by M/s Match Graphics Pvt. Ltd. and other users/décor printers. The said product is also being exported from China PR to India.

C.2. Views of the domestic industry

- 7. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and the like article are as follows:
 - a. The product under consideration is uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile of 6-12 N/15 mm and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml containing titanium dioxide or pigments as fillers. It is commonly known as decor paper, decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper. The scope excludes ready-to-use decor paper.
 - b. In market parlance, the product under consideration is defined as base paper for waxing, coating and impregnation, base paper for printing, base paper for use in decorative industry, barrier paper, and typically comes in reel sizes of 95/96/102 cm; 123/123.5/124/124.5/125 cm; 131/132 cm; 183/184/185 cm.
 - c. The full description of the product under consideration should be used in the duty table in order to avoid circumvention.
 - d. As regards the contention that duty should not be levied on the printed ready-to-use decor paper, it is submitted that the applicant did not include printed ready-to-use decor paper in the petition as the applicant does not constitute domestic industry for the same.

- e. The interested parties have not identified the product exclusion sought on the basis of titanium dioxide content. Contrary to the submissions made by the interested parties, the titanium dioxide used by the domestic industry is 'imported 100% rutile titanium dioxide, having 99% purity' and the quality of decor paper produced by the applicant is better than that imported from China PR. Lab reports showing that laminate opacity of the domestic goods is comparable to the imported goods have been provided.
- f. Regarding the contention that the Authority should mention "ready-to-use decor paper, regardless of any colour is excluded from the scope of the product under consideration", it is submitted that merely because some consumers print the paper does not mean that the product of the applicant is not ready-to-use and the same is, therefore, included within the scope.
- g. Since there are various product types involved, a PCN wise analysis is important for fair comparison. The PCNs should be based on GSM, color and application.
- h. The contention of the interested parties that the application should not be considered as a parameter for PCNs should not be accepted as the subject goods used for surfacing or liner are different from the others and have higher cost and the price due to the use of high titanium dioxide and pigments.
- i. The domestic industry has produced and sold the subject goods to the printers as well as to the laminators.
- j. Contrary to the submissions of the interested parties, the applicant has produced and sold the subject goods above 90 GSM and the same cannot be excluded from the scope of the product under consideration. The fact that the subject goods above 90 GSM are not shown on the website of the applicant is irrelevant as the sales are made through sales representatives and not through the website.
- k. The domestic industry has enclosed invoices showing that it has sold the subject goods of more than 90 GSM.
- l. The PCN-wise information provided by the domestic industry already shows that it has produced and sold the subject goods of more than 90 GSM.
- m. The subject goods are being imported under HS Codes 4805 91 00 and 4802 20 90. Contrary to the submissions by the interested parties, substantial volume of the subject goods is being imported under HS Code 4802 20 90. Accordingly, both the codes should be considered for the imposition of the anti-dumping duty. The exclusion of 4802 20 90 will lead to circumvention of the anti-dumping duty.
- n. The subject goods are normally produced and sold in terms of weight, generally in KGs or MTs.
- o. The subject goods produced by the domestic industry are the like article to the products imported from the subject country.
- p. On the contention of the interested parties that the non-imposition of the duties on the pre-printed decor paper will lead to circumvention, it is submitted that the fear of the circumvention should not lead to non-imposition of the anti-dumping duty on the subject goods. If the circumvention happens, the interested parties are free to approach the Authority.

C.3. Examination by the Authority

8. The product under consideration is uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler. It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper. Various descriptions such as base paper for waxing, coating and impregnation, base paper for printing, base paper for use in decorative industry, barrier paper and typical reel sizes 95/96/102cm; 123/123.5/124/124.5/125 cm; 131/132cm and 183/184/185 cm have been used by the exporters and the importers for importing the product under consideration.
9. The product under consideration includes decor paper used by the producers of laminates which includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color/white).
10. Decor paper is classified under the tariff entry 4805 91 00. The product under consideration is also imported under tariff entry 4802 20 90. Some of the interested parties have contended that 4802 20 90 should be excluded for imposition of the anti-dumping duty as there are negligible imports under this code and it will lead to hardship to the importers. The Authority notes that as per the evidence on record, substantial imports of the product under consideration are under the HS code 4802 20 90. Therefore, the exclusion of the said code will lead to circumvention of the anti-dumping duty. Accordingly, both the codes have been considered

for the purpose of the present investigation. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

11. Some of the interested parties have contended that the scope of product under consideration should be restricted up to 90 GSM as the domestic industry does not produce above 90 GSM. The Authority notes that as per the PCN-wise information and the evidence placed on record, the domestic industry has produced and sold the product under consideration above 90 GSM during the period of investigation and accordingly, the scope of the product under consideration includes the subject goods between the range of 40 – 130 GSM.
12. Some of the interested parties have contended that the product under consideration used directly by the laminators is not supplied by the domestic industry. The Authority notes that as per the evidence placed on record, the domestic industry has sold the subject goods to the laminators in the period of investigation and throughout the injury period.
13. The scope of the product under consideration in the present investigation excludes printed ready-to-use decor paper. While some interested parties have sought inclusion of the same in the product scope, the others have opposed. The Authority notes that the initiation notification excluded printed ready-to-use decor paper. Further, the domestic industry is not seeking imposition of the duties on the same. Therefore, the Authority opines that ready-to-use decor paper cannot be included in the scope of the product under consideration.
14. Some of the interested parties have contended that there is a difference of titanium dioxide used in the product under consideration manufactured domestically and that imported in India. However, the domestic industry has stated that it imports 100% rutile titanium dioxide having 99% purity, due to which its quality is comparable to the imported goods. The domestic industry has also submitted the test reports showing that the laminate opacity of its products is comparable to that of the goods imported from China PR. The Authority notes that the interested parties have not defined the product for which exclusion has been sought clearly. Further, no evidence has been adduced to show that the domestic industry has not produced the like article to the imported goods. Accordingly, no modification of the product scope is warranted on this account.
15. The Authority has considered the following PCN methodology for the purpose of the present investigation: -

SN	Characteristics	Code Description	Code Sign
1	GSM	Less than 50 GSM	“1”
		From 50 GSM to less than 70 GSM	“2”
		70 GSM and above	“3”
2	Colour	Coloured decor paper	“C”
		Uncoloured decor paper	“U”
3	Application	Decor paper for liner / surfacing application	“1”
		Decor paper for other applications	“2”

16. On the basis of the information on record with the Authority, the Authority notes that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the ones imported from the subject country. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the Authority finds that the subject goods produced by the domestic industry are the like article to the product under consideration imported from the subject country.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & THE STANDING

D.1. Views of the other interested parties

17. The submissions of the other interested parties with regard to the domestic industry and its standing are as follows:
 - a. ITC accepted that it had imported the subjects good during 2017-18 but the declaration and statement of the imports annexed in the application does not mention the period during which it imported the subject goods from the subject country. The Authority should verify it and disclose the same.
 - b. The applicant claimed that Shree Krishna Papers supported the application. However, no documentary evidence is available. None of the other producers have supported the application.

- c. The applicant did not disclose that Shree Krishna Paper and Industries Limited is supporting the petition, prior to oral hearing.
- d. If Shree Krishna Paper and Industries Limited is supporting the petition, it should also provide its injury information.

D.2. Views of the domestic industry

18. The following submissions have been made by the applicant with regard to the domestic industry and its standing:
 - a. The application has been filed by ITC Limited. It has not imported the subject goods from the subject country in the period of investigation and is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or the importer in India.
 - b. The applicant imported the subject goods from the subject country in 2017-18 due to shut down of its plant.
 - c. In order to upgrade its plant and machinery, the applicant's plant was shut down for about seven months in 2017-18. Accordingly, to fulfil the demand of its customers, the applicant imported the subject goods from the subject country.
 - d. The applicant accounts for a major proportion of the domestic production in India. Apart from the applicant, there are two other producers of the subject goods in India, namely, Pudumjee Paper Products Limited and Shree Krishna Paper Mills and Industries Limited.
 - e. Shree Krishna Papers has filed a support letter post initiation. In any case, the applicant alone accounts for the major proportion of the domestic production and constitutes the domestic industry even without such support.
 - f. As regards the contention that Shree Krishna Paper and Industries Limited should provide injury information, it was submitted that the applicant cannot compel any producer to do so. Even without the support of any other producer, the applicant accounts for the major production in India.

D.3. Examination by the Authority

19. The Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".
20. The application was filed by ITC Limited. It is noted that ITC Limited has imported the subject goods in 2017-18 but only ***% of the total imports in that year. However, no imports have been made during the period of investigation. It is further noted that the applicant is not related to any importer or the exporter of the subject goods in the subject country. The Authority finds that the producer is eligible to be included within the scope of the domestic industry.
21. Post the oral hearing, Shri Krishna Paper and Industries Limited has filed a letter in June, 2021 with details of the capacity, the production and the sales, supporting the imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country. However, they have not submitted the injury information. Therefore, they have not been accounted for as the domestic industry.
22. The applicant accounts for a major proportion of the domestic production.

Producer	Production (MT)	Share in production (%)	Share in production (range)
ITC Limited	***	***%	70-80
Pudumjee Paper Products Limited	***	***%	10-20
Shree Krishna Paper Mills and Industries Limited	***	***%	5-15
Total Indian production	24,227	100%	100%

23. Thus, the Authority notes that ITC Limited constitutes domestic industry under the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**E.1. Views of the other interested parties**

24. The submissions of other interested parties with regard to the confidentiality are as follows:

- a. The production share of the applicant and the other domestic producers has not been shared. The petition does not declare the value and the volume of the production and the share of the domestic producers. The basis on which the Authority decided the standing is unclear.
- b. The applicant has claimed excessive confidentiality regarding the imports in relation to the production and the consumption, sales volume, market share, installed capacity, production, capacity utilization, export sales, number of employees, productivity, etc.
- c. No data can be kept confidential automatically as held in *Sterlite Industries (India) Ltd. V. Designated Authority*. The Authority must evaluate the claim of the confidentiality as held in *HR Johnson (India) Ltd. V. Designated Authority*.
- d. Names of the raw materials, the manufacturing process, the source for total volume and the value of Indian production and the source of average industry norms for the capacity utilisation, the calculation of the normal value and the export price and the range of share in the total domestic production have not been provided. For funds raised, a reference has been made to financial statements which are unavailable.
- e. The total percentage of the imports covered by each product type and the price undercutting range for each product type has not been disclosed.
- f. The applicant has not disclosed the total period for which the plant was not operational, the actual quantity of imports by ITC, the reason for importing the product under consideration and the basis on which the adjustments were made to the data.
- g. The applicant has claimed excessive confidentiality by not providing the relevant information in the non-confidential petition. For section VI of the petition, a reference has been placed to Formats A to L but nothing has been disclosed. The justification table provided is not as per the Trade Notice.
- h. The non-injurious price has not been provided in a range of +/-10% as required in the trade notice.
- i. The purchase policy, the sales policy, the accounting policy, the cost accounting policy and the quality control procedures have been claimed confidential. The trend of the information with regard to the utility consumption, the cost of the production, the raw material and the packing material consumption has not been provided.
- j. The Authority should direct the applicant to provide the transaction-wise import data to the interested parties.

E.2. Views of the domestic industry

25. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the confidentiality:

- a. The producers / exporters have claimed excessive confidentiality by claiming the information given in the public domain as confidential.
- b. The producers / exporters have not complied with the requirements of Trade Notice 10/2018 and 01/2013.
- c. Contrary to the claims of the interested parties, the applicant has shared its share in the total production with the Authority and the Authority has examined the same as is evident from the initiation notification. As there are only three producers in the market, the disclosure of such information even in a range will provide estimate of production to the other domestic producers. The applicant has fulfilled its obligation under the Trade Notice 10/2018 by providing the best available information on an aggregate basis.
- d. The disclosure of the information with regard to the share of the applicant in the total production, the period of shutdown, the volume of the imports by the applicant, the imports in relation to the production and the consumption, the sales volume, the market share, the installed capacity, the production, the capacity utilization, the export sales, the number of employees, the productivity, etc. sought by the interested parties is of confidential nature. The interested parties have themselves not disclosed such information in their response.
- e. Contrary to the claims of the interested parties, the applicant has disclosed the names of the major raw material, the manufacturing process, the normal value and the export price in the petition. The constructed normal value is based on the business sensitive information and only the range for the constructed normal value has been shared. The financial statements of the applicant are available in the public domain and the

link for the same was shared. There is no source for the average industry norms as it is based on the market intelligence of the applicant.

- f. Regarding the contention that the methodology for the adjustment of shutdown period has not been shared, it is submitted that the applicant has followed the methodology used by the Authority for optimizing the costs. It has determined its production and the cost of production as if the plant had not shut down and allocated the fixed cost over the higher production volume.
- g. Contrary to the submissions by the interested parties, the applicant has provided justification table as per the requirements of the Trade Notice.
- h. With regard to the trends of the costing formats and the policies of the applicant, the information is business proprietary in nature and cannot be disclosed. Even the interested parties have not disclosed such information. The interested parties have claimed excessive confidentiality and not complied with the requirements of the Trade Notice 10/2018.
- i. As regards the contention that the non-injurious price has not been provided in the range of +/- 10%, it is submitted that a broader range has been shared as disclosure of non-injurious price would allow the customers to benchmark their prices and demand a lower price from the applicant.
- j. The applicant has enclosed the transaction-wise listing and the interested parties are free to obtain it by giving necessary undertaking to the Authority.

E.3. Examination by the Authority

26. With regard to confidentiality of the information, the Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

27. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
28. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of the evidence submitted by the various interested parties for inspection.
29. The interested parties have contended that the domestic industry has not disclosed its share in production, imports in relation to production and consumption, sales volume, market share, installed capacity, production, capacity utilization, export sales, number of employees, productivity, period of shutdown, volume of imports made, Formats A to L, non-injurious price, purchase policy, sales policy, accounting policy, cost accounting policy, quality control procedures, utility consumption, cost of production, raw material and packing material consumption. However, the Authority notes that such information is confidential in nature, and therefore, disclosure thereof would be prejudicial to the competitive interests of the domestic industry. Further, the Authority has accepted confidentiality claims of the producers / exporters from the subject country in respect of similar information as well.

30. The Authority further notes that contrary to the claims of the interested parties, the domestic industry has disclosed the names of the raw material, the manufacturing process, calculation of the normal value and the export price and the reasons of plant shutdown. As far as funds raised are concerned, the domestic industry has claimed that the same are not identifiable separately for the product under consideration.
31. With regard to the DGCI&S data, the Authority notes that the data has been shared with the interested parties relating to volume & value of the imports from the exporting countries into India. Further, the applicant has provided a complete list of transaction wise import data. It is also noted that any interested party can obtain data independently from the DGCI&S and lodge its own counter claim based on the data so received. The Authority holds that procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCI&S. Sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per prescribed format. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across the parties and the investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Views of the other interested parties

32. The submissions of the other interested parties with regard to the other issues are as follows:
- Para 15 of the initiation notification states that the Authority had prima facie evidence of the dumping and the injury. However, the evidence submitted must be of adequate quality to constitute “sufficient evidence”, and not prima facie evidence. The Panel in Mexico – Pipes and Tubes noted that the determination of the sufficiency must be based on an assessment of the accuracy and the adequacy of the evidence. Panel in United States – Softwood Lumber from Canada disputes held that the sufficiency means more than the mere allegations or the conjecture. In Guatemala – Cement II, the Panel noted that only the sufficient evidence of the dumping, the injury and the causation is not enough. The investigating agency should have satisfied itself of the accuracy and the adequacy of the evidence.
 - The petition is based on the suppression and the misrepresentation of the facts, and the Authority did not satisfy itself of the prima facie case by examining the adequacy and the accuracy of the petition.

F.2. Views of the domestic industry

33. The submissions of the domestic industry with regard to other issues are as following:
- Contrary to the submissions by the other interested parties, the Authority prima facie satisfied itself of the dumping, the injury and the causal link as stated in the initiation notification. The interested parties have not highlighted any instance of misrepresentation by the applicant.
 - Contrary to the claims of the interested parties, only the prima facie evidence is required at the stage of initiation as was held by the High Court in Rajasthan in Textile Mills Association V. Dir. General of Anti-Dumping and by the Tribunal in Huawei Technologies Co. Ltd. V. Designated Authority and The Automotive Tyre Manufacturer’s Association V. Designated Authority.

F.3. Examination by the Authority

34. The Authority notes that the applicant has provided a duly substantiated application, based on which the present investigation was initiated. The present investigation was initiated by the Authority based on the data/information provided by the domestic industry and prima facie satisfying itself that there is sufficient evidence of the dumping, the injury and the causal link. Further, subsequent to the initiation, the information has been sought from the applicant to the extent deemed necessary and the same has been provided by the applicant.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of the other interested parties

35. The submissions made by the other interested parties are as follows:
- China PR cannot be treated as a non-market economy as the practice of treating it as a non-market economy expired on 11th December, 2016.
 - The Indian authority should not use the surrogate country methodology in calculating the normal value for this case, regardless of not treating China PR as a market economy country.
 - The Appellate Body report in the Fastener case against EU has provided strong justification that China PR should automatically obtain the market-economy status.

- d. Following the principles of “pacta sunt servanda”, India is obligated under the international law to recognize China PR as a market economy. Article 15 of China’s accession protocol clearly establishes that no country can treat China PR as a non-market economy post 11th December, 2016. India does not have a legal basis to do otherwise.
- e. Until recently, the US and the European Union also shared the understanding that China PR would be treated as a market economy after expiry of 15 years of the Protocol.
- f. The European Union cannot be compared with China PR in terms of the level of economic development and the market conditions for the determination of the normal value. The types of decor paper in both the markets, their price and the quality must be compared. As per Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd V. Designated Authority, the level of the economic development of the market economy third country is relevant where the normal value is determined based on the price paid or payable in such country.
- g. The European Union is not an appropriate third country for the determination of the normal value as its manufacturing, labour, compliance cost, and per-capita GDP are much higher than that in China PR.
- h. The Rule clearly states that while choosing the appropriate market economy, the level of development shall be considered. If the same is disregarded, it would be inconsistent with the decision in Ku. Sonia Bhatia V. state of UP and Others, wherein it was held that every single word used by the legislature should be given importance.
- i. The Court of Justice of European Union, in Grunwald Logistik Service GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Stadt, held that the market economy should be considered as one wherein price of the product is formed in the circumstances similar to those in the country of export.
- j. The imports from the European Union to India are less than the imports from China PR.
- k. The domestic industry has not explained how the PCNs exported from the European Union are comparable to the PCNs exported from China PR.
- l. The prices of the imports from European Union are higher than the non-injurious price of the domestic industry, and the cost of production in the European Union is higher.
- m. The European Union provides the high range of shades and colors than the Chinese producers.
- n. The normal value may be constructed based on the following parameters:
 - i. Raw material consumption norm to construct the cost.
 - ii. International price of the raw material may be considered.
 - iii. Utilities cost may be worked out based on the prices in China PR.
 - iv. Interest rate prevailing in the international market including China PR may be considered.
- o. As per Paragraph 7 of Annexure I, the constructed normal value to be considered is the price from the third country to the other countries, including India and not just the export price to a single country. Hence, an average export price from a third country should be considered.
- p. The applicant during the oral hearing tried to change the methodology for the determination of the normal value from the price in the third country to the price from the third country to the other countries including India. Such a change should not be allowed without giving notice to the interested parties and seeking their comments.
- q. The determination of the normal value for the subject country contravenes Section 9(1)(c) and Annexure 1 of Anti-Dumping Rules and the adjustment made in respect of the export price is abnormally high. The Authority needed to consider such shortcoming in evidence before initiating the investigation.
- r. The data presented in the petition for the adjustment of the net export price is mere unsubstantiated assertion and could not be relied upon for the initiation. The petitioner has inflated the normal value and deflated the export price, which does not constitute the sufficient evidence to ascertain the dumping.
- s. The domestic industry has not explained how the PCNs exported by the European Union to India are comparable to the PCNs exported by China PR to India.

G.2. Views of the domestic industry

36. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.

- b. On 11th December, 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired but that of Article 15(a)(i) continue to remain in force, which require the producers to show that they are operating under the market economy conditions. The Authority has considered China PR as a non-market economy in all the recent investigations unless the exporters / producers demonstrate that they are operating under the market economy conditions.
- c. In EC-Fasteners, the issue before the Appellate Body was not specifically, whether the entire provisions of Article 15(a) or only Article 15(a)(ii) shall lapse on the expiry of 15 years and thus, reliance thereupon is not appropriate. Therefore, China PR has failed its obligation to remove the distortions and allow the price to be set by the market.
- d. Other WTO countries including the US and the European Union also treat China PR as a non-market economy.
- e. Contrary to the claims of the interested parties, the normal value is consistent with the provisions of para 7, Annexure-I of the Rules.
- f. Since no exporter has filed for a market economy status, they should be treated as operating in a non-market economy. The normal value should be determined based on the imports of European Union into India as European Union has the second largest production and consumption of the subject goods after China PR.
- g. The interested parties have not explained the reason behind the contention that the surrogate country methodology should not be used. The law provides precedence to the surrogate country methodology.
- h. Regarding the contention that Annexure I Para 7 does not mention one country but other countries and price in India could have been considered if "or" was mentioned, it is submitted that Section 9A(1)(c) provides a mandate for the Authority by using the words "shall be". However, no such mandate is given under Para 7 of Annexure-I. All the methods specified under it refer to only one country. If the price of the export from such country to the other countries is interpreted in a way to include all countries, it will become a huge exercise for the Authority. In any case, the price of the imports from the European Union is actually the price paid in India.
- i. The contention of the interested parties that the European Union should not be selected as a surrogate country due to the level of the development is incorrect as the level of development is irrelevant in case of the exports from a market economy country to India and only becomes relevant while computing the normal value based on the process in the surrogate country as held by the Tribunal in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Company V. Designated Authority. Only the volume of the exports and whether the country is dumping during the period of investigation is relevant.
- j. On the contention that all the words used by the legislature should be given importance, it is submitted that the Tribunal has held that the level of the development is relevant when determining the price prevailing in the market economy third country, but the applicant has claimed the normal value based on the price of the exports from the European Union to India.
- k. Regarding the contention that the costs are higher in the European Union and the export price is higher than the non-injurious price, it is submitted that the cost in a market economy will be higher than that in a non-market economy. There is no relevance of comparing the non-injurious price and the costs of the exporters as no consumer purchases on cost + profits basis. In any case, if the normal value is higher than the non-injurious price, the duty will be restricted to the injury margin levels.
- l. With regard to the comparability of shades and colours, the Authority has undertaken a PCN-wise analysis wherein the PCNs were decided after taking comments from the interested parties.
- m. Regarding the contention that the imports from the European Union are 10% of the total imports and are priced higher, it is submitted that the European Union is the second largest producer of the subject goods after China PR and the volume of imports from the European Union is enough to determine the normal value. The price difference does not suggest non-comparability as in most of the cases the price of the imports from a surrogate country is higher or lower than that from the subject country.
- n. In the absence of the information with regard to the prices in the European Union, the applicant has determined the normal value on the basis of the price of the exports from the European Union to India. Alternatively, the normal value has been provided on the basis of the price payable in India.
- o. Regarding the contention of the interested parties that the European Union should not be considered as a surrogate country and reliance is placed on the European Court decision, it is submitted that the Tribunal has decided the issue and the decision by the European Court cannot take precedence over it.

- p. The contention of the interested parties that the applicant tried to change the methodology for the determination of the normal value during the oral hearing is incorrect as the applicant has stated in the petition that the normal value should be constructed based on the price of the exports from the European Union to India.
- q. Contrary to the claims of the interested parties, the normal value cannot be constructed based on the price payable in India as the applicant has provided the evidence of the prices of exports from the European Union to India.
- r. Even if the Authority decides to construct the normal value, the cost of utilities and the interest rates in China PR cannot be considered as the same are distorted and the exporters have failed to demonstrate that they are operating in the market economy conditions.
- s. The export price has been derived on the basis of the import data collected from DGCI&S and the adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses to derive the net export price.
- t. The adjustments for the export price are as per the consistent practice of the Authority.
- u. Xianhe is a producer of decorative base paper as mentioned on its website. However, it has not provided the information as a producer but only as an exporter.
- v. Xianhe has stated that it produces the specialty paper. The product under consideration is also a specialty paper and a clarification is required on how the product produced by the company is different from the subject goods.
- w. Xianhe has stated that it does not have a joint venture. However, Kingdecor is a joint venture of Xianhe and Schattdecor AG.
- x. Kingdecor has a related entity in India, namely, Shah International, which is dealing in the subject goods produced by the company. If Shah International is an importer of the goods produced by Kingdecor, Part IV of the questionnaire was required to be filed. In case Shah International has acted as a sales office, the details of the selling and the distribution costs incurred by it need to be quantified and adjusted in the export price.
- y. In the anti-dumping investigation concerning imports of Non-Woven Fabric, originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR [No. 14/23/2015-DGAD], the Authority rejected the response of one of the exporters, for the reason that it had failed to disclose the existence of its office in India. Therefore, it is evident that the selling and the general and administrative expenses of the sales office in India are also required to be reduced in order to arrive at the net export price.
- z. Xianhe has stated in its response that there are no joint ventures with any other company concerning research and development, production, sales, licensing, technical and patent agreement for the product under consideration. However, its subsidiary Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. ("Kingdecor") is a joint venture with Schattdecor AG.
- aa. The Authority, in its past findings in the anti-subsidy investigations concerning imports from China PR, has consistently found that the producers in China PR benefit from access to preferential lending and utilities, including water and electricity, at less than adequate remuneration. Therefore, such rates cannot be considered for the determination of the normal value.
- bb. The comparison of the non-injurious price and the cost of the exporters is irrelevant, as no importer/consumer pays the price to the exporters depending upon the cost of the exporter.
- cc. There is no law that the normal value cannot be higher than the non-injurious price. Even if the normal value is higher than the non-injurious price, the duty would be restricted to the injury margin.
- dd. The imports from the European Union account for 10% of the total imports. These imports are more than 5% of the volume of imports from China PR and, therefore, sufficient for the determination of the normal value.

G.3. Examination by the Authority

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ('Anti-Dumping Agreement') and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

38. It is noted that while the provisions contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11th December, 2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted the information substantiating that they are operating under the market economy conditions, the normal value is required to be determined as per the provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

Determination of the Normal Value

39. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules which reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

40. The Authority notes that while the applicant has claimed that the European Union should be considered as a market economy third country, neither the applicant nor the other interested parties have provided any information and evidence to enable determination of the normal value on the basis of the price or the constructed value in the market economy third country. The Authority accordingly examined whether the

normal value can be determined based on the price of the exports from such a third country, to other countries, including India. In this regard, it is noted that while the data with regard to the exports under the concerned tariff codes is available, and further even though the DGCI&S data allows identification of the imports of the product under consideration from the European Union to India, the Authority has adopted a PCN system in order to ensure fair comparison between the normal value and the export price on the basis of the GSM, colour and application. The descriptions of the import transactions from the European Union do not permit the identification of the PCNs in all cases on the basis of the GSM, colour and application. Therefore, in the absence of accurate identification of PCN-wise information, the normal value cannot be determined based on the imports from the European Union to the other countries, including India.

41. In view of the above, the normal value for the product under consideration imported from China PR into India is determined "on other reasonable basis". The cost of production as optimized for the domestic industry after reasonable additions for the selling, general & administrative expenses and the reasonable profit margin has been considered. Accordingly, the normal value has been constructed for all the producers and the exporters in China PR for the product under consideration during the POI and the same is given in the dumping margin table below.

Determination of the Export Price

42. The followings producers / exporters from China PR have filed responses to Exporters' Questionnaire:

- i. Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.
- ii. Xianhe Co., Ltd.
- iii. Zhejiang Xianhe New Materials Sales Co., Ltd.
- iv. Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.
- v. Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.
- vi. Qifeng New Material Ltd., China PR

Export price for Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd., Xianhe Co., Ltd. and Zhejiang Xianhe New Materials Sales Co., Ltd.

Export Price

43. Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd., is a limited liability Company (a joint venture enterprise). The legal statute of Kingdecor has not changed in the last three years. During the POI, Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd., has directly exported *** MT of the PUC to India and *** MT through two different related traders, namely, Xianhe Co., Ltd. and Zhejiang Xianhe New Materials Sales Co., Ltd., China PR.
44. Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. has claimed the adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. has been determined and same is shown in dumping margin table below.

Export price for Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd., Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd. and Qifeng New Material Ltd.

45. M/s Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd. ("Ouhua"), M/s Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd. ("Oumu") and M/s Qifeng New Material Ltd. ("Qifeng") are limited liability companies by shares under the Company Law of China PR.
46. Ouhua and Oumu are related producers of the subject goods in China PR. Oumu has exported the subject goods directly to unrelated Indian customers and Ouhua has exported the subject goods to the unrelated Indian customers through Oumu and Qifeng. Oumu and Qifeng have given PCN wise details of the exports of the subject goods to India. All the three companies had provided all the relevant information in requisite formats.
47. It is noted that during the POI, Oumu has exported *** MT of self-produced subject goods and *** MT of subject goods produced by Ouhua to unrelated customer in India. Qifeng has exported *** MT of the subject goods produced by Ouhua to unrelated customer in India. Oumu and Qifeng have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost, which have been allowed by the Authority. Ouhua has invoiced subject goods to Oumu and Qifeng at ex-work basis. The Authority has verified the PCN wise details of the exports given in the questionnaire response filed by producers/exporters. The weighted average PCN wise ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

For all other producers/exporters from China PR

48. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

49. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:-

Dumping Margin Table

S.No.	Producer/Exporter	PCN	Normal Value (RS/MT)	Export Price (RS/MT)	Dumping Margin (RS/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
		China PR						
3)	Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.	1C2	***	***	***	***	***	30-40
		2C1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0-10)
		2C2	***	***	***	***	***	30-40
		2U1	***	***	***	***	***	10-20
		2U2	***	***	***	***	***	0-10
		3C1	***	***	***	***	***	10-20
		3C2	***	***	***	***	***	0-10
		3U1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0 – 10)
		3U2	***	***	***	***	***	0-10
	Total Weighted Average		***	***	***	***	***	0-10
4)	Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.	3C1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0-10)
3)	Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.	2C1	***	***	***	***	***	0-10
		2U1	***	***	***	***	***	10-20
		3C1	***	***	(***)	(***)	(***)	(20-30)
		3U1	***	***	***	***	***	0-10
	Total Weighted Average (Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd. and Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.)		***	***	***	***	***	0-10
4)	Non-cooperative/ residual exporters		***	***	***	***	***	30-40

H. ASSESSMENT OF THE INJURY AND THE CAUSAL LINK**H.1. Views of the other interested parties**

50. The submissions made by the other interested parties with regard to the injury and the causal link are as follows:
- a. Both the demand and the subject imports have increased over the injury period. The subject imports have increased due to shutdown of the plant and inability of the domestic industry to meet the demand-supply gap even after the capacity expansion.
 - b. The applicant has misled the Authority as it submitted in the oral hearing that there is no volume injury but, in the petition, claimed volume injury.
 - c. The landed value has increased over the injury period and the decline in the period of investigation is in line with the general cost and the price trends as can be seen from the data of the domestic industry.
 - d. The overall price undercutting was negative.
 - e. The claim of the domestic industry of the price undercutting based on few product types is unsubstantiated.
 - f. The domestic industry has provided manipulated data based on the secondary source, i.e., the data that the industry maintains, which has been kept confidential in order to show a positive price undercutting.
 - g. This is zeroing of only those types which demonstrate price undercutting and is not allowed under the anti-dumping laws.
 - h. The petitioner has leeway to increase the price, but it is not able to do so because of its inability to sell better grade paper due to not having the capacity, the quality of the paper, the problem of the shade variation, pulp variation, pin holes, black spot, incapability to make smaller batches, etc.
 - i. As held by the Panel in China – Definitive Anti-Dumping Duties on X-Ray Security Inspection Equipment from the European Union, in case of the negative price undercutting, the suppression or the depression cannot be attributed to the imports in the absence of cogent reasons explaining why the domestic industry could not increase its prices at least to the level of the dumped imports.
 - j. The information provided in the petition with regard to the price undercutting is insufficient as the product types considered for price undercutting are not as per PCNs prescribed. DGCI&S data has not been considered for determining the price undercutting of such types and no reason for considering the secondary data has been provided.
 - k. Both the cost of sales and the selling price of the domestic industry have decreased during the period of investigation as compared to the preceding years. The cost of production is impacted due to the capital expenditure on the additional capacity and the same should be segregated in order to arrive at the real cost of the production in the normal situation. Such cost of production will show that there is no price suppression or depression.
 - l. The capacity, the capacity utilization, the sales and the production of the domestic industry have increased over the injury period. The domestic industry is operating at optimum utilization post expansion. The capacity utilization has not declined even though the capacity had more than doubled in 2018-19.
 - m. The rate of increase in the market share of the domestic industry is higher than the rate of increase in the market share of the subject imports.
 - n. The domestic industry is selling its entire production and no additional market share is possible without the requisite capacity.
 - o. Though the inventories of the domestic industry have increased, the inventory should be analysed in terms of percentage of the production and the sales. It should be evaluated in light with increase in the capacity.
 - p. The inventories declined as a number of days of the production and the sales. In Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) V. Designated Authority, the CESTAT held that compared to the increase in the sales volume, the level of inventory has remained same percentage-wise and cannot be considered as an injury indicator.
 - q. The productivity, employment and wages have increased during the injury period. The productivity per day was highest during the period of investigation.
 - r. The cash profit of the domestic industry increased during the injury period.
 - s. The increase in the depreciation and amortization expenses shows an abnormal trend as it increased more than the increase in the installed capacity.

- t. The increase in the average capital employed is disproportionate to the increase in the installed capacity.
- u. Due to the positive parameters, the imports have not impacted the ability of the domestic industry to raise the capital investments.
- v. As held in Thailand – H-Beams, the Authority is required to evaluate all the factors before concluding the injury. In case of a positive movement of a number of factors, a compelling explanation would be required as to how the domestic industry is injured.
- w. A return of 22% on the capital employed should not be considered as the rate of 22% was considered based on Price Control Order of 1976-77, which was for a different purpose. The same should not be applied to the present case, without reference to context; the interest rates have declined since that period. Actual depreciation over the life of 20 years and the interest actually incurred should be considered.
- x. In the case of Bridge Stone Tire Manufacturing & others v. Designated Authority, it was held that the consideration of a high return at 22% results in an inflated non-injurious price. In the case of European Fertilizer Manufacturer's Association v. Council, it was held that the target price must be limited to the profit margin which the Company could reasonably count on in the normal conditions in the absence of the dumped imports.
- y. The applicant has not demonstrated the potential decline in the petition, as is required to be examined under Article 3.4.
- z. The injury to the applicant is due to the massive investment made for the capacity expansion. The applicant has not isolated the huge capital cost borne by it from the cost of production. Had the domestic industry not increased the capacity so frequently, it would have operated at optimum level.
- aa. 80% petitions filed in front of the Authority are where the domestic industry has enhanced its capacity and the injury is due to the capacity expansion.
- bb. ITC invested heavily in the capacity expansion immediately before the period of investigation and has the plans to invest more till 2025. It cannot be said that injury has been caused to any industry which is capable of investing such huge amounts.
- cc. The decline in any economic parameter is because of the increase in the capacity and not due to the subject imports as total PBIT and PBIT per unit have improved after shutdown. It remained low in 2018-19 and the period of investigation due to the increase in the capital and the fixed cost. Lower profitability and the increase in the cost of sales since 2017-18 are due to the plant shut down and the capacity expansion which led to the higher depreciation cost. The cash profits, which do not include depreciation, have improved.
- dd. The applicant was not able to command higher price due to the with the quality of the paper, the shade, etc.
- ee. The annual reports of ITC for 2019 and 2020 show positive parameters and the prospects and do not state any injury due to the dumping.
- ff. In a public statement, ITC mentioned that it will further invest in decor paper and did not allege any problem due to the dumping but blamed the covid pandemic.
- gg. The non-injurious price of the domestic industry is inflated by assuming a 26% return on all capital employed, which is unnecessarily high.
- hh. The volume of the exports by Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd., Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd. and Qifeng New Material Ltd. declined during the period of investigation and is insignificant to the total volume from China PR. The average price and the landed value of such exports is higher than that of the exports from China PR. There will be no dumping margin and the injury margin based on the average prices of the said exporters. The subject imports should be evaluated based on the increase in the demand and the available capacity of the domestic industry. The subject imports have increased due to the shutdown of the plant and the inability of the domestic industry to meet the demand-supply gap even after the capacity expansion.

H.2. Views of the domestic industry

51. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and the causal link:-
 - a. The plant of the applicant was shut down for a few months in 2017-18 as the applicant was upgrading its plant and machinery and the effect of such shutdown has been adjusted. However, the parameters for 2017-18 may not be comparable with the other years.
 - b. The volume of the subject imports has increased in the absolute and relative terms and commands majority of the imports in India.

- c. Contrary to the claims of the interested parties, the imports have not increased just because of the demand-supply gap. This is evident from the fact that the volume of imports in excess of the demand-supply gap has increased over the period. The increase in the imports is more than the increase in the demand-supply gap.
- d. The share of the subject imports in the total imports has increased over the injury period.
- e. Although the price undercutting on average basis is negative, it is positive for the three product types, constituting a major share of the imports from the subject country and the sales of the domestic industry.
- f. The price undercutting had been determined for three types of products under consideration which constitute a major share of the imports and of the sales of the domestic industry at the time of filing of the petition due to the non-availability of the PCNs at that stage.
- g. Regarding the contention that the reason for considering the secondary data has not been disclosed, it is submitted that the same was used as the product description in the DGCI&S data did not allow identification of the product type.
- h. The PCN wise undercutting should be determined according to the responses filed by the interested parties as they account for the major exports to India and the PCNs cannot be accurately determined from the DGCI&S data. PCN-wise undercutting is positive.
- i. The contention of the interested parties that zeroing is not permissible is contrary to the legal position. The Panel in European Communities – Anti-Dumping Duty on Malleable Cast Iron Tubes and Pipes from Brazil held that the undercutting may be determined on the transaction-wise basis and only on the basis of such imports that were undercutting the prices of the domestic industry. The Authority may undertake sampling for the determination of the price undercutting.
- j. Contrary to the claims of the interested parties, the subject imports have suppressed the prices of the domestic industry as the mark-up of the import price over raw material cost has declined over the period. The raw material cost has increased much more than the increase in the selling price.
- k. The subject imports had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry.
- l. Although the capacity, the production and the sales of the domestic industry have increased, the sales have not increased commensurate to the increase in the capacity.
- m. Even after selling at lower profits, the market share of the domestic industry has declined and that of the subject imports has increased.
- n. The inventories of the domestic industry have increased over the injury period.
- o. Contrary to the claims of the interested parties, the inventory as a number of days of the production or the sale has increased during the period of investigation.
- p. The profitability, the cash profits and the return on investment of the domestic industry have declined over the injury period. The applicant has earned negligible return on the investment in the period of investigation.
- q. With regard to the increase in cash profits, it is submitted that the same increased due to increase in the sales. However, it has increased much less than increase in the volume of the sales. Cash profits declined in the period of investigation as compared to the previous year. Cash profit per unit has declined over the injury period.
- r. The profits of the domestic industry have declined more than the increase in the depreciation cost.
- s. Contrary to the submissions of the interested parties, the injury cannot be attributed to the capacity expansion as it was undertaken in 2017-18 and was fully operational in 2018-19 and 2019-20. The performance of domestic industry was worse in 2019-20 as compared to 2018-19.
- t. On the contention that the capital expansion shows the lack of injury, it is submitted that the capacity expansion was undertaken in 2017-18 when the domestic industry was not suffering injury and the capacities were fully operational by 2018-19.
- u. The reference to the statement by ITC that it will invest more and is suffering due to COVID-19, it is submitted that the context of the statement showed that the applicant will invest more if the imports decline. The injury is not examined with relation to the statements made in the public domain but according to the data furnished. The reference to COVID-19 is irrelevant as the period of investigation is pre-covid period in the present investigation.

- v. The comparison between the increase in the depreciation and the capital employed cannot be made with the capacity as the former is expressed in rupees while the latter is expressed as weight.
- w. The domestic industry has suffered injury in terms of EBIDTA (Earnings before interest, depreciation, taxes and amortization) which neutralizes the impact of the increased depreciation cost.
- x. Contrary to the claims of the interested parties, the cost of the domestic industry is not inflated due to the capital expenditure. As such the cost is not added to the cost of production but capitalized. The injury to the domestic industry is due to the subject imports as the EBIDTA of the domestic industry has declined.
- y. The domestic industry has considered a 22% return on capital employed and not a 26% return. Contrary to the claims of the interested parties, the Tribunal has in a plethora of decisions consistently taken the view that unless the interested parties demonstrate the need for considering a different return, a return of 22% shall be allowed. Reference to Bridge Stone Tyre Manufacturing Vs. Designated Authority is not appropriate as in that case the interested parties brought evidence to demonstrate that the global returns for the product were less than 22%.
- z. The injury has not been caused due to any known factor but only due to the subject imports.
- aa. On the contention that the volume of imports by the participating exporters has declined and there will be no dumping margin and the injury margin, it is submitted that the Authority should verify the imports from DG Systems data as there is strong possibility of manipulating descriptions and the PCN. The injury analysis is undertaken for the subject country as a whole and not for the individual exporters.
- bb. There is no need to examine the potential decline as the applicant has already shown the actual decline in the performance and the subject goods are not sold under the long-term contracts.
- cc. The contention of the interested parties that the applicant is unable to supply quality decor paper to them is without merit. Had this been the case, the applicant would not have been able to sell the subject goods. However, it has operated at high capacity utilization levels during the injury period. Its sales volume has increased in the case of both laminators and printers. CPPRI (Central Pulp & Paper Research Institute) report and inhouse laboratory report of the applicant shows that the quality of subject goods produced by the applicant is comparable to that imported from China PR. Further, it has invested in machinery which enables it to produce best in class product quality and the same products are widely accepted by the printers and the laminators. The applicant has supplied substantial volumes of the main grades of decor paper and has the market leadership in some grades.
- dd. The sales of the applicant to the interested parties have increased over the injury period which shows that they are not facing any quality issues.
- ee. The contention that the Annual Reports of the applicant show positive parameter is misplaced as the applicant is a multi-product company and the sales of the product under consideration constitute only a small part of its business. The applicant has filed segregated information related to the product under consideration which shows the injury.

H.3. Examination by the Authority

H.3.1. Shutdown of the plant of the applicant

52. It is noted that the plant of the applicant was closed for seven months during 2017-18. The applicant has submitted that the plant shutdown was of abnormal nature as the same was done for upgradation of the plant and the machinery. To segregate the injury caused to the domestic industry due to such closure, the Authority has considered the adjusted information as submitted by the applicant after the due verification. Accordingly, the Authority has analyzed both the actual and the adjusted figures in order to evaluate the effect of the subject imports on the performance of the domestic industry.

H.3.2. Assessment of demand / apparent consumption

53. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and the other Indian producers and the imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	112	188	209

Other producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	92	108	91
Subject imports	MT	10,355	27,645	23,817	28,618	36,552
Other imports	MT	3,473	4,188	3,608	3,898	3,741
Demand	MT	28,832	42,880	42,880	55,520	63,905
Trend	Indexed	100	149	149	193	222

54. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

H.3.3. Volume effect of the dumped imports

55. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from the DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject country and the share of the dumped imports during the injury investigation period are as below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Subject imports	MT	10,355	27,645	23,817	28,618	36,552
Other imports	MT	3,473	4,188	3,608	3,898	3,741
Total	MT	13,828	31,833	27,425	32,517	40,293
Imports in relation to						
Domestic production	%	70	276	165	121	149
Consumption	%	36	64	56	52	57
Total Imports	%	75	87	87	88	91

56. It is seen that:

- The volume of the subject imports has increased throughout the injury period.
- The subject imports increased in relative terms in 2017-18, when the plant of the domestic industry faced a shutdown.
- The share of the subject imports in total imports has increased over the injury period.

H.3.4 Price effect of the dumped imports

57. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on the prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

a) Price undercutting

58. The price undercutting has been assessed by comparing the landed price of the imports with the domestic selling price in India of the subject goods. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. In order to ensure a fair comparison, the Authority has calculated the PCN-wise price undercutting which is as under. It is seen that when the PCN-wise landed price of the imports and the net sales realization are compared, the price undercutting is positive in some PCNs. As the Authority received 80 % of the exporter's response, the PCN wise landed price has been derived from the questionnaire responses of the participating exporters.

POI

S.NO	PCN No.	Net sales realization (Rs/Kg)	Landed price (Rs/Kg)	Price undercutting (Rs/Kg)	Price undercutting (%)	Price undercutting (Range)
1)	1C2	***	***	***	***	0-10
2)	2C1	***	***	***	***	20-30
3)	2C2	***	***	***	***	0-10
4)	2U1	***	***	***	***	0-10
5)	2U2	***	***	(***)	(***)	(0-10)
6)	3C1	***	***	(***)	(***)	(0-10)
7)	3C2	***	***	***	***	0-10
8)	3U1	***	***	(***)	(***)	(0-10)
9)	3U2	***	***	***	***	0-10

b) Price suppression/depression

59. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress the prices to a significant degree or prevent the price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were compared as below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	109	116	115
Raw material cost	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	137	137	120	113
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	102	109	105
Landed price	Rs./MT	1,28,861	1,36,073	1,36,073	1,39,077	1,28,817
Trend	Indexed	100	106	106	108	100

60. It is seen that the cost of sales and the raw material cost increased in 2017-18, but declined thereafter. However, both the selling price and the landed price have increased till 2018-19 but declined in the period of investigation. Over the period, the raw material cost of the domestic industry has increased and the cost of sales has increased by 15% from the base year. By comparison, the selling price of the subject goods has increased by only 5%, while the landed price has decreased. Thus, it can be concluded that the imports are suppressing the prices of the domestic industry.

H.3.5 Economic parameters of the domestic industry

61. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of the dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of the dumped imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; the actual and potential negative effects on cash

flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed hereinbelow.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

62. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	52	109	226	226
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	101	199	219
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	93	88	97
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	112	188	209
Export sales	MT	-	-	-	-	***
Trend	Indexed	-	-	-	-	100

63. The Authority notes that the capacity of the domestic industry has increased over the period, due to which the production and the domestic sales have also increased. The capacity utilization of the domestic industry declined till 2018-19 but increased during the period of investigation. Nevertheless, the capacity utilization of the domestic industry remained lower than that at the beginning of the injury period.

b) Market share

64. The market share of the domestic industry and of the imports was as shown in table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Subject imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	180	155	144	159
Other imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	70	58	49
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	40	75	98	94
Other producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	62	62	56	41
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%

65. It is seen that the market share of the domestic industry has marginally reduced during the period of investigation. The market share of the Indian producers as a whole has reduced significantly in the POI, while the market share of the subject imports has increased.

c) Inventories

66. The inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	87	33	104
Closing inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	38	38	120	194
Average inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64	64	73	146

67. It is seen that the average inventories with the domestic industry increased over the injury period, indicating accumulation of the inventories. The average level of the inventories has shown an increase of 46% in the period of investigation as compared to the base year.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

68. The profitability, the return on investment and the cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	109	116	115
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	102	109	105
Profit/(loss)	Rs./MT	***	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	(59)	37	39	10
Profits/(loss)	Rs. lakhs	***	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	(35)	41	74	21
Cash profits	Rs./MT	***	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	(42)	39	83	53
Cash profits	Rs. lakhs	***	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	(25)	44	156	111
Return on capital employed	%	***	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	(11)	13	19	6

69. The Authority notes that the domestic industry suffered losses in 2017-18, when its plant was shut down. However, its profitability improved during 2018-19 but has declined again during the period of investigation. Further, although the total cash profits have increased in the POI in comparison to the base year, the cash profits per unit have decreased. The return on capital employed has registered a significant decline during the injury period and the domestic industry earned negligible returns on the capital employed.

e) Employment, wages and productivity

70. The Authority has examined the information relating to the employment, the wages and the productivity, as given below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
No of employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	55	55	126	127
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	188	160	175
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	100	200	222
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	77	99	107
Wages per unit	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	159	76	50	49

71. It is seen that the number of employees of the domestic industry has increased over the injury period. The productivity of the domestic industry has also increased over the injury period. While the wages have increased over the injury period, the wages per unit have declined.

f) Magnitude of dumping

72. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive.

g) Growth

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Capacity	%	-	(48)	9	335	-
Production	%	-	(52)	1	311	10
Domestic sales	%	-	(40)	12	216	11
Profit/(loss) per unit	%	-	(159)	(63)	167	(74)
Cash profit	%	-	(125)	(56)	728	(29)
Return on capital employed	%	-	(111)	(87)	277	(69)

73. It is noted that the capacity, the production and the domestic sales have shown growth over the injury period. All the profitability parameters of the domestic industry showed negative growth. The profitability parameters showed growth in 2018-19 but thereafter declined again in the period of investigation.

h) Ability to raise capital investment

74. It is noted that the profits and the return on the capital employed of the domestic industry have declined in the period of investigation. This shows that the dumped imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment for the product under consideration.

i) Factors affecting prices

75. The Authority notes that the landed price of the imports declined over the injury period, and is undercutting the prices of the domestic industry, which has created a strain on the prices of the domestic industry. As a result, while the selling price of the domestic industry has increased over the injury period, such increase is less than the increase in the cost of sales of the domestic industry. Thus, the imports have affected the prices of the domestic industry.

j) Injury Margin

76. The Authority has determined the Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under

consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

77. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
78. Based on the landed price and the non-injurious price determined as above, the injury margin for the producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

Injury Margin Table

S.No.	Producer/Exporter	PCN	NIP (Rs/MT)	Landed Value (Rs/MT)	Injury Margin (Rs/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
		China PR						
1)	Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.	1C2	***	***	***	***	***	30-40
		2C1	***	***	***	***	***	0-10
		2C2	***	***	***	***	***	30-40
		2U1	***	***	***	***	***	20-30
		2U2	***	***	***	***	***	10-20
		3C1	***	***	***	***	***	20-30
		3C2	***	***	***	***	***	20-30
		3U1	***	***	***	***	***	10-20
		3U2	***	***	***	***	***	10-20
	Total Weighted Average		***	***	***	***	***	10-20
2)	Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.	3C1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0)-(10)
3)	Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.	2C1	***	***	***	***	***	10-20
		2U1	***	***	***	***	***	30-40
		3C1	***	***	(***)	(***)	(***)	(0)-(10)
		3U1	***	***	***	***	***	20-30
	Total Weighted Average (Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd. and Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.)		***	***	***	***	***	10-20
4)	Non-cooperative/residual exporters		***	***	***	***	***	50-60

H.3.6 Overall assessment of injury

79. The examination of the imports of the product under consideration and the performance of domestic industry shows that:
- i. The volume of imports has increased both in absolute terms as well as in relation to the production and the consumption in India.
 - ii. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.
 - iii. The imports have prevented the price increase which otherwise would have occurred.
 - iv. The production, the sales and the capacity of the domestic industry increased.
 - v. The market share of the domestic industry and the Indian industry as a whole has declined while that of the subject imports has increased over the injury period.
 - vi. The average level of inventories of the domestic industry has increased over the injury period.
 - vii. The profits and the cash profits per unit of the domestic industry have declined over the injury period.
 - viii. The return on the capital employed of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry is earning only nominal return on the capital employed.
 - ix. While the volume parameters of the domestic industry have shown growth, the profitability parameters have shown negative growth.
 - x. The imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments of the product under consideration.
 - xi. The dumping margin is positive and significant.
80. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered the material injury.

H.3.7 Non-attribution analysis and the casual link

81. Having examined the existence of the injury, the volume and the price effects of the dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor other than the dumped imports as listed under the Rules.

a) Volume and value of imports from third countries

82. It is seen that other than the subject country imports, the major imports of the subject goods are from the European Union. However, such imports are priced much more than the price of the subject imports. Further, the price of the imports from the European Union is higher than the selling price of the domestic industry. Other than the subject country and the European Union, the imports from other countries are negligible in volume. Thus, it cannot be said that the imports from the other countries are causing injury.

b) Contraction in demand

83. The Authority notes that there is no contraction in the demand as the demand of the subject goods in the country has consistently grown throughout the injury period. Thus, the domestic industry has not suffered any injury on this account.

c) Pattern of consumption

84. It is noted that there is no change in the pattern of consumption of the subject goods which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

85. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or the trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

86. The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

f) Productivity

87. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

g) Export performance of the domestic industry

88. The Authority notes that the domestic industry has exported a small share of its production in the period of investigation. However, the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h) Performance of other products

89. The Authority has only considered the data relating to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

H.3.8 Conclusions on the causal link

90. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.

- a. There is significant dumping of the subject goods in India.
- b. The volume of dumped imports has increased in absolute terms as well as in relation to the production and the consumption during the period of investigation.
- c. As a result, the market share of the subject imports has increased and that of the domestic industry decreased.
- d. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- e. The imports have suppressed the prices of the domestic industry by preventing it from increasing its selling price commensurate to the increase in its cost of sales.
- f. The profits and cash profits per unit have declined over the injury period.
- g. The return on capital employed of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry is earning only a nominal return on the capital employed.

91. Some of the interested parties have argued that the domestic industry has suffered injury due to the capacity expansion. In this regard, it is noted that the domestic industry the completed capacity expansion in 2017-18, post which its performance improved in 2018-19. However, the performance of the domestic industry has declined again during the period of investigation, which cannot be attributed to capacity expansion. Further, the EBIDTA (Earnings before interest, depreciation, taxes and amortization) of the domestic industry, which is not impacted by the increased depreciation or the finance cost, has been adversely impacted as well in the present period. Therefore, the injury suffered cannot be attributed to the capacity expansion.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
EBIDTA (Earnings before interest, depreciation, taxes and amortization)	Rs./MT	***	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	(42)	39	83	53

92. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumped subject goods and the injury to the domestic industry.

I. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS**I.1 Views of the other interested parties**

93. The following post-disclosure submissions have been made by the other interested parties:

- a. The Authority should exclude the petitioner from the scope of the domestic industry as it has imported substantial quantity of the product under consideration. The Rule 2(b) does not have any mandate to restrict the examination of the imports made only during the period of investigation.
- b. Since the price undercutting is negative, the injury to the domestic industry cannot be attributed to the dumped imports.

- c. The return on capital employed of the petitioner is not negative. The low profitability of the domestic industry is due to its incapability of taking orders for small batches for colours, as it needs a minimum order quantity of 30 tons as compared to 5 tons for China PR or 1 ton for the European Union.
- d. The disclosure statement does not disclose how the effect of the capital cost/finance cost of the capacity enhancement has been treated for determining the optimized cost of production, which has been adopted for determination of the normal value.
- e. The ex-factory export price for Ouhua has not been determined correctly. Since Oumu and Qifeng are extended arms of Ouhua, no deductions are required to be made for profit and indirect SGA expenses incurred by them for determining the ex-factory export price for the subject goods manufactured by Ouhua.
- f. The anti-dumping duty will be detrimental to the interest of the small-scale users which order in batches of 5 MT or less as the domestic industry has insufficient capacity to service the entire demand and is unwilling to take orders below 30MT.
- g. The PCN wise price undercutting cannot be relied upon unless all the import transactions are accounted for. Merely because the responding parties account for 80% of the total imports into India, it cannot be assumed that they are representative of the PCN wise import trend for the remaining 20% of the imports.
- h. The anti-dumping duty will lead to adverse impact on the users as their profit margins is extremely less. The product under consideration accounts for approximately 6% of the total cost of the production of the finished goods in which it is used. The profit margin for Deco Mica is merely 1.4%, while that for AICA it is merely 8%.
- i. The un-dumped imports should not be considered for the purpose of the volume and the price analysis.
- j. The weighted average price undercutting at the product level and country level has not been disclosed.
- k. The methodology for the determination of the normal value for the product types/PCNs not manufactured by the domestic industry should be disclosed.
- l. The dumping margin determined for PCN 2UI is very high. The constructed normal value determined on the basis of the cost of production of the domestic industry is exaggerated and not reflective of the actual cost of production.

I.2. Views of the domestic industry

94. The following post-disclosure submissions have been made by the domestic industry:

- a. Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited is also suffering injury due to dumping of the subject imports as its production, capacity utilisation and the domestic sales have declined over the injury period.
- b. The effect of the anti-dumping measures on the public interest must be studied from the perspective of the interests of different set of parties including domestic producers, consumers, upstream and downstream industries and the general public.
- c. The Indian industry for the product under consideration consists of three producers. In case the dumping is not checked and the injury continues, the petitioner will have to close its operations which will result in the users being substantially dependent on the imports.
- d. The laminates industry has grown multifold in terms of the exports from Rs. 500 crores in 2012 to Rs. 2,000 crores in 2020. If the anti-dumping duty is imposed and thus the imported PUC is available at fair price, the laminates industry would prefer buying the PUC from the domestic producers. That will strengthen the value chain for the domestic laminates industry.
- e. The domestic industry produces product under consideration of high quality and the consumers can fully trust the indigenously produced product.
- f. While the petitioner has a long term interest in the Indian market as it has been a known name in India since 1910 and is involved in the various markets, the exporters interest is limited to maximizing profits. The exporters will not hesitate to exit a market in case better prices are available to them.
- g. Since the time lag between placing the order and getting the delivery is much more in the case of imports, the users will have to maintain large inventories of the subject goods. This will increase the costs of the users.

I.3. Examination of the Authority

95. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and the domestic industry and notes that though most comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the findings, the Authority has examined the fresh issues raised by the interested parties.
- a. With regard to the contention that the Authority should exclude the petitioner from the scope of the domestic industry as it has imported substantial quantity of the product under consideration, it is noted that petitioner has imported the product under consideration in 2017-18 only upto 7% of the total imports in that year. However, no imports have been made during the period of investigation. Also, the Rule 2(b) specifically refers to eligibility of such producers who *"are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof"*. Also, the applicant is not related to any importer or the exporter of the subject goods in the subject country. Thus, the Authority finds that the producer is eligible to be included within the scope of the domestic industry.
 - b. With regard to the negative price undercutting for some of the PCNs, the Authority notes that the price undercutting is one of the injury parameters. As concluded hereinabove, the prices of the subject imports have created a strain and have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry. The profitability parameters of the domestic industry have been adversely impacted due to the dumping of the subject imports.
 - c. With regard to the return on the capital employed not being negative, it is noted that the Annexure – II requires the Authority to determine whether there has been a natural and potential decline in the return on the capital employed. This implies that if there is a decline in the return on the capital employed, the Authority may conclude that the domestic industry has suffered injury in terms of that parameter, even if the return is positive.
 - d. With regard to the treatment of the capital cost / finance cost to determine the cost of production / non-injurious price of the domestic industry, the Authority notes that the cost incurred for the capital expenditure has not been added to the cost of production, but has been capitalized, in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India. Further, the domestic industry has not claimed any finance cost. Thus, the cost of production of the domestic industry is appropriately determined and is not exaggerated.
 - e. With regard to the determination of the net export price for Ouhua, the Authority notes that since it is exporting the subject goods to India through related entities, Oumu and Qifeng, the profit and indirect SGA expenses incurred by the related entities are required to be adjusted in order to determine the net export price for Ouhua, in accordance with the consistent practice of the Authority.
 - f. With regard to adverse impact of imposition of anti-dumping duty on the users, as their profit margin is low, the Authority has examined the profits of the users as per financial statements. The profits of users do not show any correlation to the landed price of imports. The users have claimed low margins even though the landed price of imports has declined over the period. The users have not shown that they suffered losses, when the price of imports was higher. To the contrary, the summary of financial statements of the users, as brought on record by the domestic industry, shows that the profit margin of the users was higher during the periods when the import price was higher. Therefore, it cannot be considered that the increase in prices would result in the users incurring losses.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS & OTHER ISSUES

J.1. Views by the other interested parties

96. The submissions made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest are as follows:
- a. The decor paper printing industry is in the process of establishing itself in India. It is forced to import the product under consideration due to limited supply options and the non-availability of the required quality of the print base paper.
 - b. The quality of print base paper made by the domestic industry does not match the quality parameter of the user industry in terms of smoothness and colour absorption capacity which leads to high rejection rates. Therefore, the users are forced to import the product.
 - c. There cannot be an apple to apple comparison between the imported goods and the domestic goods in terms of quality. Any rejection of the decor paper due to the quality does not fetch any value to the printers.

- d. The printers face stiff competition from the pre-printed decor paper as they need to import the print base paper, printing inks, ink binders, machineries, equipment, printing cylinders, etc. which adds to their cost.
- e. The imposition of the duties only on the product under consideration will make the printed decor paper from the subject country cheaper, which will lead to the printers facing stiff price competition. It may result in the dumping of such product, leading to extinction of the Indian printing industry, which would adversely impact the domestic industry.
- f. The imposition of the anti-dumping duty on the imports of the product under consideration will give decor printers from the subject country undue competitive advantage over the domestic printers. In case the imports of the pre-printed decor paper accelerate, many domestic printers may have to shut down which will be against the Make in India initiative.
- g. The imposition of the anti-dumping duty will not be in the public interest as despite being the largest producer of the decor paper, the applicant is not able to meet the demand in the country and there is a huge demand-supply gap. Therefore, the imports are inevitable and the users will be forced to pay duties on such imports. The subject goods are consumed by a large number of downstream users, mostly in the MSME sector.
- h. Even after the expansion of the capacities and operating at 100% capacity utilisation, the domestic industry can meet only 50% of the domestic demand. In such a case, the only objective of invoking the anti-dumping law is to attain super normal profits to recover the capital cost.

J.2. Views by the domestic industry

97. The submissions made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest are as follows:

- a. If the injury to the applicant continues for long, the applicant may have to shut down its operations and the consumers will have to substantially depend upon on imports.
- b. The users have not demonstrated any likely adverse impact of the imposition of the anti-dumping duty on their performance.
- c. The imposition of the anti-dumping duty will not significantly impact the user interest as impact on the prices of the downstream industry will be insignificant and it will be able to pass on such increase to the consumers.
- d. The performance of the users is not dependent upon the price of the imports as their performance was best in 2016-17 when the mark up of the subject goods over the raw material prices was highest and the domestic industry did not suffer any injury. The users were unaffected when the prices of the imports were higher. The performance of users has shown a decline with decline in the landed price.
- e. It cannot be construed that the operations of the users would become unviable due to availability of the goods at fair prices. The users cannot claim a right to availability of goods at dumped prices.
- f. The applicant has invested a significant amount for the capacity expansion in order to move towards Aatma Nirbhar India. It is necessary to provide a level playing field to protect such investment and encourage further investment in order to reduce the demand-supply gap in the country.
- g. It is necessary for the applicant to earn adequate profits in order to recover the investment and the cost of investment as the decor paper industry is capital intensive in nature. Currently, the profits of the applicant are inadequate to cover more than 10% of the cost of the financing.
- h. The imposition of the anti-dumping duty would encourage investment in the product and help bridge the demand-supply gap.
- i. Regarding the contention that there is a demand-supply gap in the country and the only objective of the anti-dumping duty is to attain super normal profits, it is submitted that the imposition of the anti-dumping duty will not restrict the availability of the subject goods in India but only establish a fair competition in the market. In *Nocil Limited V. Government of India*, the High Court held that demand-supply gap is not a justification for dumping. The CESTAT in *DSM Idemitsu Limited V. Designated Authority* held that the exporters cannot dump on the pretext that the domestic industry was not in a position to meet the demand in India. The Authority has consistently recommended imposition of the anti-dumping duty even in the cases where there was a demand-supply gap.
- j. The support provided by the Government of China PR to the producers / exporters has destroyed the fair competition in India. The producers / exporters acknowledge that their costs and prices are affected by the Chinese government intervention which is evident from the fact that none of the parties have filed for a market economy treatment.

- k. The challenges identified by the interested parties include that they are forced to import the subject goods, but the applicant is offering the same domestically.

J.3. Examination by the Authority

98. As per the data available on record, the sales of the domestic industry have increased, which indicates that the goods sold by the domestic industry are of the requisite quality. The user industry has not furnished any information regarding the parameters in which the products produced by the domestic industry do not match the imported products. However, as per the Central Pulp and Paper Research Institute (CPPRI) report, the parameters of the goods imported in India and the parameters of the goods sold by the domestic industry have a trivial difference in the quality of the subject goods.
99. Some of the interested parties have contended that if the duties are not imposed on the pre-printed decor paper, the dumping of the same will start. The Authority notes that the present investigation pertains to the imports of the product under consideration which excludes pre-printed decor paper. In case the dumping of the pre-printed decor paper starts, the domestic producers are free to approach the Authority for imposition of the anti-dumping duty on the said product.
100. Some interested parties have contended that the imports are inevitable due to the demand-supply gap in India and they would be forced to pay higher price for the imports. The Authority notes that the demand-supply gap is not a justification for dumping in India. Even if there is a demand-supply gap in the country, it is necessary that the product is available at fair prices. The imposition of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at the fair prices. In fact, the re-establishment of fair competition in the market may encourage further investment, which would help further bridge the demand-supply gap.
101. Further, the domestic industry has submitted that the product can also be imported from other countries such as Italy, Japan, Germany and Poland, along with sourcing the goods domestically. In any case, there are only three producers of the subject goods in the country, of which the petitioner is the largest producer. If the current situation persists, the viability of the operations of the domestic industry may be impacted. Therefore, to ensure continued availability of domestic product, it is necessary that the domestic producers remain viable at fair prices, failing which the users would become increasingly dependent on the dumped imports. The recent experience in the Covid-19 period has also shown that the users suffer if they are substantially dependent on the imports.
102. With regard to the operations of the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has shown long-term commitment to the production in India. Considering the significant demand in the country, the domestic industry invested a significant sum to increase capacities. That being the case, it needs to earn adequate profits, in order to recover its investment. However, at present, its profits are significantly low. The domestic industry has highlighted that had it financed its plant through loans, the profits earned at present would cover only 10% of the finance cost, even assuming an interest rate of 9%. Therefore, such a market situation would not be conducive to encouraging further investment in the country.
103. The users have also claimed that the imposition of duties would adversely impact their margins, as the product under consideration constitutes 6% of their cost of production, and they are operating at low margins. The domestic industry has claimed that the impact of duties on the users would be 0.66% to 1.64%. Even assuming that the product under consideration constitutes 6% of the cost of production of the users, the Authority notes that the duty recommended is less than 10%. In view of the same, the Authority finds that the duty would lead to an increase of at best 0.6%, which cannot be considered significant.
104. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, the fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of a wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of the anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product under consideration to the consumers.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

105. Having regard to the contentions raised, the information provided, the submissions made and the facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:

- i. The product produced by the domestic industry is the like article to the product under consideration imported from the subject country.
- ii. The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of investigation and the application contained sufficient evidence to justify the initiation of the investigation.
- iii. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin has been determined for the subject country. The dumping margin is positive and significant.
- iv. The domestic industry has suffered material injury. The examination of subject imports and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of the subject imports has increased in absolute terms despite the significant capacity addition by the domestic industry. The imports are suppressing the prices of the domestic industry. The profitability parameters of the domestic industry have shown a negative growth over the injury period.
- v. The injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.
- vi. The information on record shows that the non-imposition of the anti-dumping duty will adversely and materially impact the indigenous production, while imposition of the duty will not materially impact the consumers or the downstream industry or the public at large. On the basis of the information provided by the interested parties and the investigation conducted, the Authority is of the considered view that the imposition of the anti-dumping duty will not be against the public interest.

106. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers and the other interested parties to provide the positive information on the aspect of the dumping, the injury, the causal link and the impact of proposed measures. Having initiated and conducted the investigation into the dumping, the injury and the causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that the imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and the injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.

107. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of the custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S.No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	48059100, 48022090	Decor Paper*	China PR	China PR	Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.	116	MT	US\$
2.	48059100, 48022090	Decor Paper*	China PR	China PR	Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd. and Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.	110	MT	US\$
3.	48059100, 48022090	Decor Paper*	China PR	Any country including China PR	Any other than Sl No. 1 and 2	542	MT	US\$
4.	48059100, 48022090	Decor Paper*	Any country other than China PR	China PR	Any	542	MT	US\$

**uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler. It includes base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decor paper, decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper. The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white). It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.*

L. FURTHER PROCEDURE

108. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate Forum.

ANANT SWARUP, Designated Authority